बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 300

बजट में परमाणु ऊर्जा पर ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि देश में 'स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए यह आवश्यक' है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के नाम से एक खास पहल की जाएगी जिसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। देर से ही सही मगर सरकार ने यह महसूस किया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के ऊर्जा स्रोतों में तत्काल विविधता लाने की जरूरत है। शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के गति पकड़ने और गर्मी में तापमान अत्यधिक बढ़ने से पिछले एक दशक के दौरान देश में बिजली की मांग खासी बढ़ गई है। फिलहाल देश में बिजली की कुल मांग का 89 प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म ईंधन से आ रहा है। ऊर्जा के दूसरे वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा की राह में तकनीकी एवं मूल्य नीतियों से जुड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं। बजट में घोषित इस मिशन के अंतर्गत 2033 तक पांच छोटे आकार के मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये सभी उच्च क्षमता वाले रिएक्टर होंगे जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावॉट (ई) प्रति यूनिट या परंपरागत परमाणु बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता की एक तिहाई होगी। पिछले महीने अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड पर लगी पाबंदियां हटा दी थीं। भारत अमेरिका के इस कदम का तेजी से लाभ उठाना चाहता है।

भारत में वर्ष 2024 में 8.18 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2014 में दर्ज 4.78 गीगावॉट उत्पादन के दोगुने से थोड़ा ही अधिक था। अगले 22 वर्षों में 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। सरकार एसएमआर में निजी क्षेत्र से निवेश पर निर्भर दिखाई दे रही है। निजी क्षेत्र पर निर्भरता इस बात से भी झलकती है कि सरकार नियंत्रित भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए रकम का आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 472 करोड़ रुपये घटा दिया गया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट भी 402 करोड़ रुपये कम कर दिया है। निजी क्षेत्र से निवेश स्वीकार करने की तत्परता दिखाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए) में संशोधन करेगी। पहले कानून में संशोधन के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एनपीसीआईएल का बोलबाला खत्म हो जाएगा। संभव है कि सरकार उस शर्त का समाधान निकालने की कोशिश करेगी जिससे भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद दुनिया में निजी क्षेत्र की परमाणु ऊर्जा कंपनियां निवेश के लिए आगे नहीं आ रही हैं। इस समझौते के अंतर्गत किसी परमाणु दुर्घटना से हुए नुकसान की सूरत में आपूर्तिकर्ताओं और परिचालनकर्ताओं की जवाबदेही तय की गई थी।

एसएमआर तकनीक अपेक्षाकृत नई जरूर है मगर भारत छोटे रिएक्टर तैयार करने और इनका परिचालन करने में अपनी क्षमता की बखूबी नुमाइश कर चुका है। देश में स्थानीय स्तर पर तैयार एवं परिचालन करने वाले 22 परमाणु रिएक्टरों में से ज्यादातर की क्षमता रेटिंग 220 मेगावॉट (ई) है। भारत को परमाणु ऊर्जा से संचालित अपनी पनडुब्बी के लिए 85 एमडब्ल्यूई संयंत्र तैयार करने का भी अनुभव है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत डिजाइन टीम एक मॉड्यूलर संयंत्र प्रक्रिया में देश के इस अनुभव का लाभ उठाने में जुटा हुई है। इससे निजी क्षेत्र की इकाइयों के साथ तकनीक साझा करने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। रिएक्टर तेजी से स्थापित करने, लागत में कमी, सुरक्षा चाक-चौबंद रखने की ताकत और रिएक्टरों की स्थापना में लचीलापन जैसी खूबियां होने के बावजूद कई दूसरी तरह की बाधाएं एसएमआर से जुड़ी भारत की महत्त्वाकांक्षाओं की राह में अवरोध पैदा कर सकती हैं। इन बाधाओं में लाइसेंस देने की मौजूदा व्यवस्था और ग्रिड-पावर प्राइसिंग का पुराना झमेला भी शामिल हैं। ग्रिड-पावर प्राइसिंग की दिक्कत तीन दशकों से अधिक समय से बिजली उत्पादन इकाइयों को चोट पहुंचा रही है। अधिकांश विश्लेषकों को लगता है कि अगले 22 वर्षों में 100 गीगावॉट परमाणु बिजली क्षमता के विकास उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा।

अजय मोहंती

कर राहत, पारदर्शिता और नए वादों का बजट

वित्त मंत्री ने बजट में कर राहत देने के साथ देश-विदेश की चुनौतियों के बीच जिस कौशल के साथ वित्तीय संसाधनों को संभाला है और आंकड़ों पर जो पारदर्शिता दिखाई है वह सराहनीय है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा छाया हुआ है। चर्चा का विषय देश के करीब 4.3 करोड़ आयकरदाताओं को मिली कर राहत है। वित्त मंत्री ने उन्हें कुल 1 लाख करोड़ रुपये की राहत दी है, जो केंद्र के कर राजस्व की करीब 2.5 फीसदी बैठती है। एक ही बार में इतनी बड़ी आयकर राहत इस देश में पहले कभी नहीं दी गई है, इसलिए इसकी चर्चा होनी लाजिमी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार सातवें पूर्ण बजट में अलग-अलग आय वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरें ही नहीं घटाई गईं बल्कि मध्य वर्ग को कई दूसरी राहत भी दी गईं। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए आसान नियम भी इसमें शामिल हैं, जिनसे करदाताओं पर बोझ घटेगा। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती देखकर उठाए गए हैं ताकि कर घटने से खपत बढ़े और वृद्धि भी पटरी पर लौटे। यह तो समय ही बताएगा कि छोटी सी आबादी को आयकर में दी गई भारी छूट से खपत कितनी बढ़ी और मांग तथा वृद्धि में कितना इजाफा हुआ।

किंतु यह बजट आयकर में राहत देने तक ही नहीं सिमटा है। देश-विदेश से आ रही चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री ने केंद्र सराकर के वित्तीय संसाधनों को जैसे संभाला और इस्तेमाल किया है वह सराहनीय है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार ने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मार्के की बात है। संशोधित अनुमानों में सरकार का शुद्ध राजस्व बजट अनुमान से 1.3 फीसदी कम हो गया। व्यक्तिगत आयकर संग्रह तेजी से बढ़ा मगर कॉरपोरेशन कर तथा गैर कर प्राप्तियां कम होने से संग्रह कम रह गया। इसकी भरपाई व्यय में 2 फीसदी कटौती से हो गई, जो पूंजीगत व्यय में 8 फीसदी कमी का नतीजा थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यय की गुणवत्ता कई साल बाद बिगड़ी है मगर राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 फीसदी पर रोक लिया गया, जिसके लिए पिछले बजट में 4.9 फीसदी का अनुमान लगाया गया था।

वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 फीसदी तक समेटने का लक्ष्य रखा गया है, जो सीतारमण द्वारा 2021 में रखे गए लक्ष्य से भी 10 आधार अंक कम है। अगले वित्त वर्ष में कंपनी कर में 10 फीसदी बढ़ोतरी के अनुमान पर सवाल उठाए जा सकते हैं क्योंकि 2024-25 में इसमें 7.5 फीसदी वृद्धि ही हो रही है। मगर ध्यान रहे कि अनुमान यह मानकर लगाया गया है कि वित्त वर्ष में 10.1 फीसदी नॉमिनल आर्थिक वृद्धि होगी। अलबत्ता व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 14 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान वास्तविक प्रतीत होता है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 फीसदी इजाफा हुआ है। व्यय के मामले में वित्त मंत्री ने मुट्ठी अधिक नहीं खोली है और 2025-26 के लिए इसे 7.4 फीसदी बढ़ाकर 50 लाख करोड़ रुपये पर ही समेट दिया है। इसमें 39 लाख करोड़ रुपये राजस्व व्यय (6.6 फीसदी अधिक) और 11.2 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय (उम्मीद से बेहद कम 10 फीसदी बढ़ोतरी) शामिल है।

वित्त मंत्री ने 2026-27 से अगले पांच साल तक राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सार्वजनिक ऋण में कटौती का सहारा लेने की बात बजट में कही है। कोई बड़ा झटका नहीं लगा तो सरकार राजकोषीय घाटा इस तरह कम करने का प्रयास करेगी कि सार्वजनिक ऋण का बोझ लगातार घटते हुए 31 मार्च 2031 तक जीडीपी के 50 फीसदी पर सिमट जाए। चालू वित्त वर्ष में यह जीडीपी का 57.1 फीसदी है। खजाने को मजबूती देने का रास्ता और तरीका ज्यादा स्पष्ट करना सही रहेगा। उदाहरण के लिए सरकार को बताना चाहिए कि ऋण के आंकड़ों के साथ वह राजकोषीय घाटे का निश्चित स्तर या दायरा भी बताएगी अथवा नहीं।

बजट में सरकार ने पूरी पारदर्शिता भी बरती है। सराकर ने साफ बताया है कि बजट के अलावा दूसरे स्रोतों से कितनी उधारी ली जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में शून्य उधारी थी और अगले दो वित्त वर्षों में भी शून्य रहने का ही अनुमान है। व्यावसायिक तरीके से चलने वाले कुछ केंद्रीय उपक्रमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों पर देनदारी के बारे में अतिरिक्त जानकारी की ही तरह यह भी राहत की बात है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) पर चढ़ा कर्ज कम हो रहा है। एनएचएआई पर कर्ज 2021-22 में 3.48 लाख करोड़ रुपये हो गया था और 2022-23 में आईआरएफसी का कर्ज 4.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। ऐसी जानकारी से राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ेगी और सार्वजनिक वित्त की स्थिति ज्यादा साफ हो जाएगी।

2025-26 के बजट में यह भी बताया गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिले धन में से कितनी रकम खर्च होने से बच गई है। इन योजनाओं के लिए आवंटित रकम में से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये 31 दिसंबर, 2024 तक राज्यों के पास पड़े होने का अनुमान है। यह छोटी रकम नहीं है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सालाना व्यय के 40 फीसदी से अधिक है। ऐसी जानकारी से सरकार को बची हुई कुल रकम और राज्यों की खर्च करने की क्षमता के हिसाब से खर्च का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। साथ ही राज्यों के व्यय की जवाबदेही भी तय होती है और उन्हें बताया जाता है कि कम खर्च होने पर संशोधित अनुमान में उनका आवंटन कम क्यों हो सकता है। जाहिर है कि इन खुलासों से जागरूकता बढ़ती है और कुछ योजनाओं के तहत रकम को बिना खर्च छोड़ने के बजाय इस सीमित संसाधन का अधिक उत्पादक कामों में इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है। ऐसे खुलासों से शायद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में शहरी आवास, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, स्वच्छ भारत अभियान या जल जीवन अभियान जैसी बड़ी योजनाओं के लिए बजट अनुमान की तुलना में आवंटन एकदम कम क्यों हो गया है।

वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 के बजट में किए पांच वादों में से चार पूरे कर दिए। एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। सीमा शुल्क को वाजिब बनाया जा रहा है, जिससे 26 वस्तुओं (मोटरसाइकल सहित) पर सीमा शुल्क घटा है। साथ ही 14 वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क दरों में कमी हुई है और 37 वस्तुओं पर भी शुल्क दरें कम हुई हैं। एक नई आयकर प्रणाली आई है और राजकोष को मजबूत करने का ऋण आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है। बजट में बिजली वितरण, शहरी क्षेत्र, नियामकीय ढांचा, खनन, कराधान और बीमा (जिसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है) में सुधारों का जिक्र किया गया है। बस, पूंजी, श्रम, जमीन जैसे फैक्टर मार्केट में दूसरे चरण के सुधारों के लिए कदम अभी बताए जाने हैं।

हां, अफसोस की बात है कि बजट में रणनीतिक विनिवेश पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इसमें सार्वजनिक परिसंपत्तियां बेचकर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नई परियोजनाओं में करने का जिक्र भर है। अगले पांच वर्षों में इससे 10 लाख करोड़ रुपये जुटने का अनुमान है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द ही विनिवेश सरकार की अहम योजनाओं में वापस जगह बना लेगा।

नकद आरक्षी अनुपात में कमी की जरूरत नहीं

बैंकिंग तंत्र में उपलब्ध अधिशेष तरलता या नकदी दिसंबर 2024 का दूसरा पखवाड़ा आते-आते रफूचक्कर हो गई और इसमें कमी का सिलसिला शुरू हो गया। 20 जनवरी तक बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की कमी बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार द्वारा जमा की गई भारी भरकम रकम भी कुछ हद तक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। शुद्ध अधिशेष टिकाऊ नकदी (दीर्घकालिक नकदी) भी 27 दिसंबर तक कम होकर 64,350 करोड़ रुपये ही रह गई, जो 26 जुलाई को 4.20 लाख करोड़ रुपये थी। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण बैंकिंग प्रणाली से भी बड़ी मात्रा में रुपया निकल गया। रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार में 27 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 के बीच 4 अरब डॉलर की कमी और आ गई। इसलिए टिकाऊ नकदी भी अब तक कमी में तब्दील हो गई होगी।

नकदी में कमी आने की आशंका को रिजर्व बैंक पहले ही भांप गया था, इसीलिए दिसंबर में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद उसने सभी बैंकों के लिए नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) दो बार 25-25 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग एवं समय देयता (एनटीडीएल) का 4 प्रतिशत कर दिया। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आ गई।

कुछ वित्तीय समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक हाल में हुई एक बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों ने रिजर्व बैंक को सुझाव दिया कि सीआरआर में और कटौती करते हुए टिकाऊ नकदी का इंतजाम किया जा सकता है। सीआरआर अब ऐसे गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है जहां अतिरिक्त कटौती करने से पहले अत्यंत सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है।

अतीत में मौद्रिक प्रबंधन उपाय के रूप में सीआरआर का इस्तेमाल आरक्षित मुद्रा प्रसार सीमित करने के लिए किया जाता था मगर अब इससे दो लक्ष्य साधे जा रहे हैं। पहला, सीआरआर की मदद से रिजर्व बैंक के पास बैंकों के खातों में निपटान रकम (भुगतान देनदारियां पूरी करने में इस्तेमाल होने वाली रकम) में अचानक हुई बढ़ोतरी या निकासी को नियंत्रण में रखकर अल्प अवधि की दरों पर अंकुश लगाए रखने में मदद मिलती है। बैंकों में काम-काज की अवधि समाप्त होने पर सीआरआर का तय स्तर बरकरार रखना अनिवार्य होता है मगर कारोबारी अवधि के बीच बैंक इस रकम का इस्तेमाल निपटान के लिए कर सकते हैं और करते भी हैं। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की अनिवार्य रकम जितनी कम रहती है बैंकों के पास ओवरनाइट लिक्विडिटी डेफिसिट का जोखिम उठाए बिना कामकाजी अवधि (इंट्रा-पीरियड) में आरक्षित रकम प्रबंधित करने की गुंजाइश उतनी ही कम होती है। इतना ही नहीं, दिन के अंत में किसी तरह की कमी की भरपाई सीआरआर रकम से की जा सकती है क्योंकि किसी पखवाड़े में सीआरआर का औसत स्तर बरकरार रखना होता है (मगर रोजाना निर्धारित सीआरआर का न्यूनतम 90 प्रतिशत स्तर बनाए रखना भी अनिवार्य है)। इससे ओवरनाइट इंटर-बैंक कॉल मनी रेट पर दबाव कम हो जाता है। ओवरनाइट इंटर बैंक कॉल मनी रेट मौद्रिक नीति का कामकाजी लक्ष्य होता है। अल्प अवधि की ब्याज दरें स्थिर रखने के उद्देश्य से आरक्षित नकदी की जरूरत अनिवार्य तौर पर या स्वैच्छिक तौर पर लागू की जाती है। दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी यह व्यवस्था है।

जनक राज

तेजी से उभरते बाजारों में नकद आरक्षी अनुपात की शर्त रखने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण बड़े स्तर पर और रकम की अचानक आवक से जुड़ी चिंताओं से निपटना है। हाल के वर्षों में ऐसे दो मौके आए हैं, जब रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार को शांत करने के लिए काफी कम समय में बड़ी मात्रा में नकदी डालनी पड़ी। पहला मौका 2008 में आया, जब उत्तर अटलांटिक वित्तीय संकट पैदा हुआ था। उस समय रिजर्व बैंक ने एनडीटीएल के 15 प्रतिशत से अधिक के बराबर नकदी उपलब्ध कराई थी या इस तरह के उपायों की घोषणा की। इनमें सीआरआर 9 प्रतिशत में 4 प्रतिशत की कटौती भी शामिल थी, जिसके बाद यह 5 प्रतिशत ही रह गया था।

दूसरा मौका कोविड-19 महामारी के दौरान आया था जब रिजर्व बैंक ने 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक नकदी (भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत के बराबर रकम, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक तो केवल बैंकों के लिए थी) उपलब्ध कराई थी। यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि जून 1973 में जब से सीआरआर में पहली बार संशोधन कर इसे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया तब से केवल एक अपवाद को छोड़कर इसे एनटीडीएल का 4 प्रतिशत से कम नहीं होने दिया गया। केवल कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 में इसे 100 आधार अंक घटाकर एनटीडीएल का 3 प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि सीआरआर पहले ही गंभीर स्तर पर था इसलिए एकबारगी उपाय के तौर पर इसे कम किया गया मगर एक साल के भीतर ही इसे दोबारा 4 प्रतिशत कर दिया गया।

संकट के समय सीआरआर में कमी के जरिये वित्तीय तंत्र में तेजी से और दीर्घकालिक नकदी डाली जा सकती है। सीआरआर में यह स्वतंत्रता और छूट देती है, जो दूसरे उपायों में अक्सर नहीं दिखती है। उदाहरण के लिए खुले बाजार में परिचालन (ओएमओ) के जरिये टिकाऊ नकदी उपलब्ध कराना एक धीमी प्रक्रिया है, जिससे एक बार में बड़ी मात्रा में रकम उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। ओएमओ के साथ दूसरी समस्या यह है कि इसमें अधिक सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां रखने वाले बैंक ही भाग ले सकते हैं।

बड़े ओएमओ सरकारी प्रतिभूतियों या बॉन्ड पर यील्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ब्याज दर के पूरे ढांचे में भी भारी उथल-पुथल ला सकते हैं। दूसरे उपायों से अलग सीआरआर के माध्यम से टिकाऊ नकदी तेजी से उपलब्ध कराने में रिजर्व बैंक को कामकाज से जुड़ी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका प्रभाव भी सभी बैंकों पर समान रूप से होता है। वास्तव में चालू पखवाड़े में भी सीआरआर में कमी का विकल्प मौजूद रहता है क्योंकि इसकी निर्धारित सीमा एक पखवाड़ा रुककर प्रभाव में आती है। इस वजह से रिजर्व बैंक को वित्तीय प्रणाली में तत्काल नकदी उपलब्ध कराने में आसानी होती है।

फिलहाल सीआरआर में और कमी की गुंजाइश दिख रही है और दूसरी बात यह है कि हम किसी संकट से भी नहीं गुजर रहे हैं। इन बातों पर विचार करते हुए सीआरआर 4 प्रतिशत से नीचे करना समझदारी वाला कदम नहीं माना जा सकता। वैसे भी मौजूदा नकदी संकट अस्थायी है, जो समय के साथ दूर हो जाएगा। ऐसे हालात से निपटने के लिए रिजर्व बैंक की नियमित नकदी समायोजन व्यवस्था ही काफी है। अगर दीर्घ अवधि के लिए नकदी डालने की जरूरत पेश आई तब भी दूसरे उपायों पर विचार किया जा सकता है।

(लेखक सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस, नई दिल्ली में वरिष्ठ फेलो हैं)

आपका पक्ष

एआई की दौड़ में भारत भी शामिल

चीन द्वारा एआई डीपसीक लॉन्च किए जाने के बाद एआई तकनीकी कंपनियों में मची उथल-पुथल से भारत को अपने तकनीकी क्षेत्र में व्यापक सुधार का संदेश देती है। अगर भारत को चीन और अमेरिका के साथ इस दौड़ में शामिल होना है तो उसे प्रतिभा पलायन को रोककर उनका समुचित उपयोग को बढ़ावा देना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिभा के मामले में भारत एक वैश्विक महाशक्ति है। यहां हर साल लाखों अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 15 लाख इंजीनियरिंग छात्र स्नातक बनते हैं। अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के जरिये भारतीय प्रतिभाओं ने विश्व की सॉफ्टवेयर कंपनियों में अपना परचम लहराया है। इसके विपरीत भारत स्वयं उनकी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिभाओं के अनुकूल आर्थिक एवं कार्य क्षेत्र का माहौल विकसित किया जाए जिससे उनका पलायन रुके। भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.64 प्रतिशत ही शोध एवं विकास पर खर्च करता है। इसके मुकाबले अमेरिका शोध एवं विकास पर अपने जीडीपी का 3.4 प्रतिशत एवं चीन 2.41 प्रतिशत खर्च करता है। अमेरिका के मुकाबले भारत का शोध पर खर्च मात्र 20 फीसदी ही है। अतः भारत को तकनीकी शोध एवं विकास पर खर्च को बढ़ाना होगा।

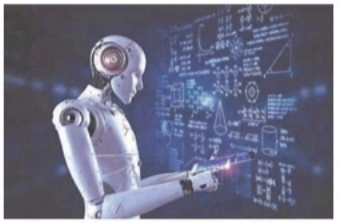

विमलेश पगारिया, बदनावर

भारत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिभा के मामले में दुनिया की बड़ी ताकत है

बदलता मौसम चक्र और बढ़ता तापमान

मौसम में ज्यादा बदलाव अर्थात अधिक गर्मी और अधिक ठंड का होना तथा मौसम के अपने निर्धारित माह में नहीं आना चिंताजनक है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण में बदलाव का बुरा असर लकड़ी पर भी हो रहा है। उसकी प्रकृति बदल रही है और उससे बनने वाले वाद्ययंत्रों में मधुर स्वर नहीं आएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संगीत थेरेपी द्वारा संगीत सुनाकर पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों को पूर्ण स्वस्थ एवं विकसित करने के प्रयोग जारी है जिसके सफल परिणाम भी सामने आए हैं। पर्यावरण में बदलाव को सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। इसके लिए पौधरोपण ज्यादा करने तथा वृक्षों को कटने नहीं देना होगा। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। पूर्व में जलवायु पर हुए डरबन अंतर-राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के संबंध में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाने से जनाक्रोश भी उभर कर सामने आया था। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि खाद्यान्न, बायो ईंधन हो या कागज हर चीज लकड़ी और उससे पैदा करने वाले जंगलों पर आकर ठहर जाती है। वहीं इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में कई हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी जो निश्चित तौर पर जंगलों को काट कर प्राप्त की जाएगी। वृक्षों से ताप का नियंत्रण होता है साथ ही वायुमंडल की विषाक्तता भी कम हो जाती है। जितने अधिक वृक्ष होंगे उतना वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ होगा। भविष्य में हरित क्रांति को विलुप्त होने से बचाने के लिए पौधरोपण की अनिवार्यता व वृक्षों को काटने से बचाना ही सही तरीका होगा।

संजय वर्मा, मनावर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के 100 साल पूरे होने पर रविवार को राज्यरानी एक्सप्रेस का संचालन पूरी तरह महिला चालक दल द्वारा किया गया।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 3 फरवरी 2025

फिर से व्यापार युद्ध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए टैक्स छूट के तोहफे से मध्य वर्ग को खुश कर दिया। इससे खपत में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर जिस तरह के व्यापार युद्ध की शुरुआत की है, उसका असर भारत पर भी हो सकता है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

ट्रंप : बढ़ी अनिश्चितता

बढ़ सकती है उलझन | ट्रंप की इन घोषणाओं के बाद इन देशों की ओर से जवाबी कदमों का ऐलान स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप इन देशों तक ही रुकने वाले नहीं हैं। यूरोप उनके अजेंडे पर पहले से ही रहा है। इससे अनिश्चितता पैदा हो रही है। देखना होगा कि यह सिलसिला किस तरफ और कितना आगे बढ़ता है।

भारत की रणनीतिः भारत इस मामले में फिलहाल रक्षात्मक रुख अपनाते हुए बढ़ता दिख रहा है। इसकी ठोस वजहें भी हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप भारत से ट्रेड सरप्लस कम करने को कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ी नरमी दिखाकर और अमेरिका से हथियार, तेल, गैस और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाकर उन्हें शांत किया जा सकता है। यह इसलिए भी संभव दिखता है क्योंकि ट्रंप की प्राथमिकताएं अभी अलग हैं। लैटिन अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और रूस से निपटना उनके अजेंडे में ऊपर है।

असमंजस कम नहीं | बावजूद इसके, भारत के लिए नरमी के इस रुख पर कायम रहना आसान नहीं होगा। अगर भारत सिर्फ अमेरिका को आयात शुल्क में रियायत देता है तो वह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के खिलाफ होगा। ये नियम कहते हैं कि सभी देशों के लिए टैरिफ समान होना चाहिए। लेकिन अगर भारत सभी देशों को आयात शुल्क में छूट देता है तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का लक्ष्य कमजोर होगा।

ग्लोबल असर | सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते जो व्यापार युद्ध शुरू होगा, उसका ग्लोबल इकॉनमी पर नकारात्मक असर होगा। इससे भारत में विदेशी निवेश का फ्लो कम हो सकता है, रुपये में और गिरावट आ सकती है। बजट से उपजा उत्साह अपनी जगह है, लेकिन आने वाली इन चुनौतियों के मद्देनजर अभी से तैयारी करनी होगी। स्वाभाविक ही, इसी हफ्ते रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों पर होने वाली घोषणाओं पर निगाहें टिक गई हैं।

चक्र-व्यू

किस ओर तुम

राहुल पाण्डेय

मेरे एक पुराने साहित्यकार मित्र परेशान हैं। दिल्ली में इन दिनों विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। मित्रवर पशोपेश में हैं कि जाएं या ना जाएं। सुबह फोन पर बताने लगे कि अगर जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, सेल्फी खिंचाने लगते हैं। लोगों से किसी तरह से निजात पाते हैं तो लेखक घेर लेते हैं, विमोचन कराने लगते हैं। जिस किताब की विषयवस्तु ही नहीं पता, उसका विमोचन कैसे किया जा सकता है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें विमोचन की बीमारी है। एक पुराने आलोचक थे। आलोचना में उनका बड़ा नाम था, हालांकि आलोचक महोदय अब नहीं हैं। वह पुस्तक मेले में सिर्फ विमोचन करने जाते थे। किसी भी दिन अगर उन्हें चार से कम किताबें विमोचन करने के लिए मिलती थीं तो ऐसे बेचैन हो जाते थे, जैसे पान खाने वाले को घंटों पान ना मिले। या फिर जैसे चाय पीने की तलब लगी हो, लेकिन किचन में चायपत्ती का डिब्बा खाली निकले।

खैर, मित्रवर डर रहे हैं कि पुस्तक मेले में पहुंचे और कोई उन्हें पकड़कर अपनी किताब का विमोचन न करा ले। मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप सोशल मीडिया पर ऐलान कर दीजिए कि आप दिल्ली में हैं ही नहीं। कहीं और की कोई पुरानी फोटो डाल दीजिए। और नहीं तो पिछले माघ मेले में जब आप संगम गए थे, वही वाली फोटो डाल दीजिए। उसके बाद आप मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी लगाकर मेरे साथ चले चलिए। बोले, आइडिया तो ठीक है, लेकिन कविगण ज्यादा घाघ होते हैं। वे चिलमन के पीछे से भी सबको पहचान लेते हैं। कविताएं उनकी भले ही तीखी ना हों, मगर बात जब काव्य संग्रह के विमोचन की हो तो उनकी नजर बिलकुल भी भोथरी नहीं होती। पुस्तक मेले में आप किसी से टकरा जाइए, चल जाएगा। लेकिन अगर किसी कवि ने आपको घेर लिया तो सबसे पहले गुटबाजी के आरोप लगते हैं। इन दिनों तो ऐसे आरोप पहले से ही फैशन में चल रहे हैं। हालात यूं हैं कि लेखक अकेला चले, तो भी कहने लगते हैं कि तय करो किस ओर हो तुम, आदमी की ओर हो, या कि आदमखोर हो तुम!

एकदा

औषधि की खोज

गुरुकुल के दिनों की बात है। चरक ऋषि अपनी शिक्षा के दौरान गहन अध्ययन और कठोर परिश्रम में लगे रहते थे। एक दिन उनके पैर में एक फोड़ा हो गया और इससे काफी दर्द होने लगा। उन्होंने अपनी इस समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरु पुनर्वसु आत्रेय ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, 'वत्स, इस फोड़े का उपचार एक विशेष औषधि से संभव है। वह औषधि जंगल में पाई जाती है। तुम्हें उसे खोजकर लाना होगा।' कई दिनों तक जंगलों में भटककर चरक ने विभिन्न पौधों और जड़ी-बूटियों का निरीक्षण किया। जब औषधि नहीं मिली, तब थक-हारकर वह गुरुकुल लौट आए। गुरुजी के समक्ष खड़े होकर उन्होंने अपनी असफलता की पूरी कहानी कह सुनाई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'वत्स, जिस औषधि की तुम्हें खोज थी, वह तो यहीं, आश्रम के पीछे ही मौजूद थी।' चरक ने हैरान होकर पूछा, 'गुरुजी, जब औषधि यहीं थी, तो आपने मुझे जंगल में भेजा ही क्यों?' गुरुजी ने समझाया, 'बेटा, औषधि कहां मिली, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि तुमने उसे पाने के लिए कितने प्रयास किए। तुम्हारे फोड़े का दर्द तुम्हारे लिए असहनीय था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। यही प्रयास और यही जिज्ञासा तुम्हें एक दिन महान वैद्य बनाएगी। जीवन में मेहनत, धैर्य और लगन बहुत जरूरी हैं। गुरुजी की बातों ने चरक ऋषि के मन में गहरी छाप छोड़ी। वह जीवनभर खोज में लगे रहे और उन्होंने वैद्य का जीवन जिया।

संकलन : रिंकल शर्मा

वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों से ग्रोथ की उम्मीद बढ़ी तो कुछ सवाल भी खड़े हुए

कहां से आया मध्य वर्ग को टैक्स छूट का पैसा

नीलकंठ मिश्रा

पिछले तीन दशकों में सरकार के दखल में काफी कमी आई है। लेकिन लोगों के मन से पुराने दौर की यादें मिटी नहीं हैं। तब बजट से लोगों की उम्मीदें उफान पर होती थीं। उसी याद की वजह से आज भी लोग बजट से काफी उम्मीदें लगाए रहते हैं। अगर इस बार के बजट की बात करें तो वित्तीय अनुशासन के दबाव की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी।

सस्ता कर्ज | उन्होंने वित्त वर्ष 2026 में बजट घाटे के अनुमान को GDP के 4.5% से भी कम रखा। वित्तीय अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सरकार को सस्ता कर्ज मिलता है।

बजट का क्या होगा असर
- वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखना बड़ी बात
- मध्य वर्ग को छूट से खपत बढ़ने की आस
- आने वाले वर्षों में खर्च बढ़ाना होगा आसान

खर्च का अनुशासन | सरकार ने वित्तीय घाटे को लेकर जो वादा चार साल पहले किया था, उसे पूरा किया है। इससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। वित्तीय घाटा कम करने को लेकर उसने आने वाले पांच वर्षों के लिए भी एक लक्ष्य रखा है। कर्ज और GDP अनुपात के रूप में सरकार ने अपने लिए कुछ आजादी भी रखी हुई है ताकि मुश्किल वक्त में खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया जा सके।

भरोसा बढ़ा | यही नहीं, वित्त मंत्री ने ग्रोथ और कर संग्रह को लेकर जो अनुमान तय किए हैं, उससे भी सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसकी अहमियत यूं समझिए कि मार्केट को अब बजट के इस पहलू पर टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं लगता। देश ने पहले ऐसा भी दौर देखा है, जब कर संग्रह का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर लगाया जाता था, जिससे सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते थे।

कैपेक्स की हकीकत | कोविड महामारी का दौर गुजरे वक्त हो गया। इसलिए इस बजट की तुलना कोविड से पहले यानी वित्त वर्ष 2019 के बजट से करना मुनासिब होगा। अगर आप इन दो बजट की तुलना करें तो कुछ हैरतंगेज बदलाव दिखेंगे। पहली बात तो यही है कि टैक्स और GDP के अनुपात में बढ़िया सुधार हुआ है। दूसरी तरफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा निवेश हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे यह स्थिति बदल जाए। वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में इसके संकेत तब मिले, जब सरकार के पास खर्च करने के अवसरों की कमी हो गई। संविधान के मुताबिक, यह पैसा नैशनल हाइवेज, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर ही खर्च किया जा सकता है। नैशनल हाइवेज बनने की आज जो रफ्तार है, उस लिहाज से हर 10 साल पर इसका पूरा नेटवर्क फिर से तैयार किया जा सकता है। रेलवे में भी निवेश करने की सीमा है और BSNL को 4G इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाना था, वह पूरा हो चुका है। इसलिए सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ठिकाने नहीं बचे हैं।

शहरों में निवेश | वैसे, देश को शहरों और पर्यटन केंद्रों में भारी निवेश करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए बजट में ऐसे खर्च का जिक्र भी किया। लेकिन ये क्षेत्र मुख्य रूप से राज्यों के अधीन आते हैं। इसलिए इनमें निवेश को केंद्र सरकार सीधे नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी तरफ, राज्यों को इनमें निवेश की खातिर प्रोत्साहित करने के लिए इन्सेंटिव देने होंगे।

डिमांड मजबूत होगी | बजट के हिसाब-किताब के मुताबिक, सरकार के पास सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपये को मनचाही चीजों पर खर्च करने का विकल्प था और उसने इसका इस्तेमाल 12 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने के लिए किया। हमारा मानना है कि इस छूट का बड़ा फायदा मध्य वर्ग को मिलेगा। और उसके इस पैसे को खर्च करने से मांग को मजबूती मिलेगी, जो अभी कमजोर दिख रही है। हो सकता है कि टैक्स में बचत के आधार पर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लें तो कुल डिमांड पर सरकार के इस उपाय का असर कहीं ज्यादा होगा।

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस | बजट में सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं। उसने कंप्लायंस बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई चीजों को गैर-आपराधिक करार दिया है। फाइलिंग्स को आसान बनाया है। इनसे सरकार पर आमदनी के लिहाज से कोई खास असर नहीं होगा, साथ ही प्रॉडक्टिविटी बढ़ेगी। राज्य सरकारें अब 2 लाख करोड़ रुपये की रकम जनता को ट्रांसफर कर सकती हैं। हमारा मानना है कि इसमें से ज्यादातर पैसा खाने की चीजों पर खर्च हो रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि विनिवेश और निजीकरण को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मुझे लगता है कि इन पर फिर से गौर करने की जरूरत है। इन उपायों से सरकार को अपना कर्ज घटाने में और मदद मिलेगी। ऐसे में उसके लिए मुश्किल वक्त में खर्च बढ़ाना आसान हो जाएगा।

(लेखक एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

विकसित भारत की ओर कितने क़दम बढ़े

लुइस मिरांडा

देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है कि आर्थिक ग्रोथ सुस्त पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ना और पश्चिमी देशों में बढ़ता संरक्षणवाद भी बड़े चैलेंज हैं। इन सबके बीच मोदी सरकार ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य तय किए हैं। आइए, जानते हैं कि इस बजट में जो उपाय किए गए हैं, उनसे इस लक्ष्य के करीब पहुंचने में कितनी मदद मिलेगी?

मध्य वर्ग को राहत | मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है, लेकिन देखना होगा कि इससे खपत बढ़ाने में किस हद तक मदद मिलती है।

रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स | बजट में रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स के लिए हाई लेवल कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। देश को ऐसे रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। यूं तो बजट में यह नहीं बताया गया कि सरकार के अंदर रिफॉर्म्स होंगे या नहीं, फिर भी ऐसे कई प्रस्तावों का ऐलान किया गया है, जिनका बहुत ही अच्छा असर हो सकता है। कुछ ऐसे कदमों का भी ऐलान हुआ, जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। मसलन, बीमा क्षेत्र में 100% FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की घोषणा तो हुई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर ये शर्तें न लगाई जातीं तो यह कदम कहीं बेहतर होता।

राज्यों का सूचकांक | राज्यों में निवेश आकर्षित करने वाला सूचकांक पेंडिंग है। इसके बनने से राज्य अपने यहां अधिक से अधिक निवेश हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' की खातिर काफी कुछ हुआ है। यह पहल जारी रहनी चाहिए।

ऐसे और कानून चाहिए | केंद्र ने जन विश्वास (संशोधन) कानून, 2023 लागू किया था। उसके बाद कई कानूनों को गैर-आपराधिक बनाने की जरूरत थी। इसकी पहल बजट में हुई है। इस तरह के और कानून लाए जाने चाहिए। वहीं, नौकरशाहों को बिना CBI, CVC, CAG आदि के डर के फैसले लेने की आजादी मिलनी चाहिए। जानबूझ कर और अनजाने में हुई गलती के बीच फर्क किया जाना चाहिए। इसे सरकार के अंदर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में लागू करने की जरूरत है।

विनिवेश पर चुप्पी | हैरानी की बात है कि बजट में विनिवेश का जिक्र नहीं हुआ। यह निराशा वाली बात है क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार को कई क्षेत्रों से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरी ओर, विनिवेश से जो पैसा आएगा, केंद्र उसका इस्तेमाल विकास की खातिर कर सकता है।

कृषि सुधार हों | निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में खेती, MSME, निवेश और निर्यात पर फोकस किया। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें वैसे सुधारों की दरकार है, जिसका प्रस्ताव सरकार ने साल 2020 में किया था। अगर वह दूसरे राजनीतिक दलों से बात करके इन सुधारों पर सहमति बना पाती है और उसे लागू करती है तो अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

ग्रोथ कैसे आएगी
- खपत बढ़ेगी या नहीं, यह अभी देखना होगा
- कृषि क्षेत्र में सुधार पर सहमति बनाए सरकार
- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस पर पहल जारी रहे

MSME को क्या चाहिए | MSME को फंड जुटाने में जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे दूर करने के लिए बजट में उपाय किए गए हैं। लेकिन इनकी दिक्कत सिर्फ यही नहीं है। ध्यान रहे, छोटी कंपनियों पर अक्सर बड़ी कंपनियां अपनी शर्तें थोपती हैं। सरकार और बड़ी कंपनियों की ओर से इन्हें भुगतान में भी देरी होती है। इससे ऐसी कंपनियों की परेशानी बढ़ती है।

कुशल श्रमिकों की कमी | द स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए भी कर्ज लेना संभव हुआ है। लेकिन यह बात भी छिपी नहीं है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कई राज्यों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पष्ट कानून नहीं हैं न ही उनके लिए प्रक्रिया परिभाषित है। निवेश की बात करें तो बजट में लोगों को हुनरमंद बनाने की खातिर खर्च करने की बात है। यह बात भी सच है कि देश में कुशल श्रमिकों की कमी है और बेरोजगारी दर ज्यादा है। दशकों से श्रमिकों को कुशल बनाने की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में नतीजा अपेक्षित नहीं रहा है।

उच्च शिक्षा | औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति बहुत धीमी रही है। वैसे, पिछले 10 वर्षों में 1.1 लाख मेडिकल सीटें बढ़ी हैं और नए वित्त वर्ष में भी इनमें 10 हजार की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। यह अच्छा कदम है, लेकिन भारत को इससे कहीं अधिक डॉक्टरों की जरूरत है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों का दायित्व तय करना होगा। देखना होगा कि वे किस तरह के नतीजे दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए नए तरह से स्कूल की जरूरत है।

(लेखक इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के चेयरपर्सन हैं)

लंबी अवधि के निवेश का क्या होगा

धीरेंद्र कुमार

आखिरकार देश को ऐसा बजट मिल ही गया, जिससे मध्य वर्ग वाकई खुश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा को नई टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जो वेतनभोगी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12.75 लाख रुपये बैठता है। मध्य वर्ग के लिए यह राहत ऐसे समय में आई है, जब वह ऊंची महंगाई दर और आर्थिक उलझनों से घिरा हुआ है। इससे बजट में किए गए इस उपाय से खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास दर में भी तेजी आएगी।

टैक्स छूट की सीमा बढ़ने से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। उनके हाथ में खर्च करने के लिए पहले से अधिक पैसा बचेगा। इससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की महंगाई का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति होम लोन पर EMI दे रहा है या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की प्लानिंग कर रहा है तो उसे टैक्स में दी गई इस राहत से मासिक खर्च को संभालने में मदद मिलेगी।

भारत की टैक्स व्यवस्था पेचीदा है। ऐसे में नई टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब तय किए गए हैं, उसने इसे आसान बनाया है। 2020 में नई टैक्स रिजीम की घोषणा की गई थी। उसके बाद से हर गुजरते साल के साथ सिंपल होने की वजह से इसका आकर्षण बढ़ता गया है। नई टैक्स रिजीम की बुनियाद सहज है। इसमें टैक्स दरें कम हैं। टैक्स छूट के मद भी कम हैं। अप्रोच भी सिंपल है। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए लोगों को बहुत माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। सरकार अगर इस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है तो भविष्य को लेकर उसकी सोच स्पष्ट है। वह चाहती है कि आगे चलकर एक आम नागरिक के लिए टैक्स कंप्लायंस बहुत आसान हो। एक नए सेंट्रल KYC (नो योर कस्टमर) रजिस्ट्री की भी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। अभी इसके लिए जो व्यवस्था है, उसमें निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के लिए बार-बार KYC की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। अगर सेंट्रल KYC की व्यवस्था होगी तो इससे फाइनैंशल असेट्स में निवेश बढ़ सकता है।

AI Image

लेकिन इन उपायों के साथ निवेश पर टैक्स में छूट वाली व्यवस्था से हम जिस तरह से पीछे हट रहे हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। भारत में खपत आधारित अर्थव्यवस्था है। यहां निवेश पर छूट वाली व्यवस्था की वजह से कम उम्र में लोग बचत करने के लिए प्रेरित होते रहे हैं। इसके साथ उनकी शुरुआत होती है, जो ताउम्र एक आदत में बदल जाती है। खासतौर पर इससे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में काफी पैसा आता है। इस तरह के फंड में किए गए निवेश पर टैक्स छूट के साथ ऐतिहासिक रूप से इक्विटी से ऊंचे रिटर्न का भी लाभ मिलता है।

खैर, बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से खपत में तेजी आएगी, जो देश की आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि टैक्स व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। निवेश पर टैक्स छूट की योजनाओं में लॉक इन पीरियड होता है। इससे लोगों में धीरज आता है। वे यह भी सीखते हैं कि लंबी अवधि के निवेश से कैसे बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हफ्ते भर के अंदर टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इन सबके बीच लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित भी करते रहना होगा। NPS की कामयाबी ने यह दिखाया है कि प्रॉडक्ट अच्छा हो तो उससे व्यक्ति के साथ देश का भी फायदा होता है।

(लेखक वैल्यू रिसर्च के सीईओ हैं)

मन में उमंग हो, तो जीवन में वसंत आ ही जाता है

गोपाल अग्रवाल

मानव जीवन में ज्ञान का स्थान अतुलनीय है। जिस तरह से मौसम कभी एक जैसा नहीं रह सकता, उसी तरह से कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता। सीखने की हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। प्रकृति जैसे सर्दियों की कठोरता से उबरते हुए वसंत की मधुरता में बदल जाती है, वैसे ही मनुष्य का अंदरूनी संसार भी निरंतर विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में ज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह हमें हमारे भीतरी कोमल विचारों, भावनाओं और बौद्धिक क्षमताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है।

ज्ञान हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देता है, जहां हम अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि मन, शरीर और आत्मा की एकता में ही पूर्णता है।

ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे अंधेरे कोनों में छिपे प्रश्नों के उत्तर खोजने में हमारी सहायता करता है। यह न केवल हमारे दिमाग की क्षमताओं को विकसित करता है, बल्कि हमारे दिल को भी समझदारी, सहानुभूति और करुणा से भर देता है। जिनमें करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, उनमें ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान और करुणा किसी कॉम्बो पैक की तरह हैं, हमेशा साथ ही आते हैं।

अक्सर हमें समाज के मानदंडों और अपेक्षाओं के दबाव में अपने वास्तविक स्वभाव को भूलना पड़ता है। ऐसे में आंतरिक जागरूकता और स्वयं की खोज हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। वसंत में सरसों के पीले-पीले फूल खेतों में ही नहीं खिलते, ये हमारे मन पर भी छा जाते हैं। यह बताता है कि सत्य की खोज केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियों और अनुभवों के माध्यम से भी होती है।

जब हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के अनुभवों, भावनाओं और आध्यात्मिक उन्नति का भी आईना है। ज्ञान हमें इस सत्य की ओर ले जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने आप को जानना और समझना है। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को अपनाते हैं, तो न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपने आस-पास के संसार में भी एक सकारात्मक बदलाव की लहर उत्पन्न करते हैं। ठीक वैसा ही बदलाव, जैसा कि वसंत इन दिनों लेकर आया है। पत्ते-पत्ते में उमंग है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि यही विकसित होने का सही समय है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

टूडो का नजरिया बदले

31 जनवरी का संपादकीय 'सही निकला भारत' पढ़ा। 2023 में हुई खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम ट्रुडो ने भारत पर कई बेतुके आरोप लगाए थे। भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया और उनसे आरोपों के सबूत मांगे। लेकिन ट्रुडो एक भी सबूत नहीं दे पाए। कनाडा के इन बेतुके आरोपों को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में भी तल्खियां भी देखने को मिलीं। अब कनाडाई आयोग की रिपोर्ट ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडाई पीएम कनाडा की जमीन पर फल-फूल रहे भारत विरोधी खालिस्तानियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे।

पैंथर तोमर, किशन गंज

टैक्स छूट अच्छा फैसला

इस बार का आम बजट राहत भरा रहा, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए। पहली बार सरकार ने इस वर्ग के हितों पर गहराई से ध्यान दिया है, जिससे विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से खपत बढ़ेगी और इकॉनमी को नई रफ्तार मिलेगी। कृषि, विज्ञान, रक्षा, स्वास्थ्य और दवाइयों के क्षेत्र में सरकार की ईमानदार सोच स्पष्ट झलकती है। युवाओं के रोजगार के लिए उठाए गए कदम लाभकारी सिद्ध होंगे। भविष्य में भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी।

हरिहर सिंह चौहान, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बजट पर बोले राहुल, गोली के घाव पर मरहम पट्टी का प्रयास- एक खबर
– जब इरादा ठीक है तो इलाज के रास्ते भी निकलेंगे।

प्रियंका रावत

चीन की प्रगति

अमेरिका को चुनौती

चीन की तेजी से प्रगति अमेरिकन वर्चस्व को पहले के किसी भी समय की तुलना में बड़ी चुनौती है जो 'डीपसीक' जैसे प्रयासों से स्पष्ट है। दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका अद्यतन तकनीकों में दुनिया का नेता रहा है जिनमें कृत्रिम बुद्धि-एआई से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तथा रक्षा खोजों से लेकर अंतरिक्ष खोज तक शामिल हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में चीन की तेज प्रगति को राज्य-संचालित पहलों, प्रतिभा अधिग्रहण तथा आक्रामक आरएंडडी निवेशों से बढ़ावा मिला है और आज वह अमेरिकन वर्चस्व को गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। 'ओपेनएआई' के 'जीपीटी-4' माडल के मुकाबले चीनी एआई माडल 'डीपसीक' का उभार केवल एक उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि बीजिंग यह तकनीकी खाई पाट रहा है। चीन की महत्वाकांक्षायें एआई से आगे जाती हैं। उसने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह चीन के 'विज़न 2025' का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो अब यथार्थ में बदल रहा है। चीन ने 'जियूझियांग क्वांटम कंप्यूटर' विकसित किया है जिसने परंपरागत सुपरकंप्यूटरों की तुलना में कंप्यूटेशनल गति को असाधारण रूप से तेज कर दिया है। इस बीच अमेरिका भी गूगल और आईबीएम जैसी कंपनियों के माध्यम से अपनी क्वांटम खोज में लगा है, पर चीन का सरकार-समर्थित दृष्टिकोण दीर्घकालीन नियोजन में सहायता करता है। अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को धोखा देने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर एआई-संचालित युद्ध क्षमताओं तक चीन के सैनिक आधुनिकीकरण ने वैश्विक शक्ति गतिशीलता बदली है।

चीन के सुपरकंप्यूटर उद्योग को पंगु बनाने को लक्षित अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद बीजिंग ने उल्लेखनीय प्रगति की है जिसमें हुवावेई की '7 एनएम किरिन चिप' शामिल है। यह उम्मीद से बहुत अधिक है। अमेरिका ताइवान की टीएसएमसी पर निर्भर है, पर चीन द्वारा आत्मनिर्भरता के अथक प्रयासों से यह खाई पाटी जा रही है। अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भी चीन प्रगति कर रहा है। चीन का तियानगांग स्पेस स्टेशन, उसके मंगल व चंद्र खोज कार्यक्रमों तथा महत्वाकांक्षी उपग्रह-आधारित इंटरनेट ने नासा और स्पेसएक्स को कड़ी टक्कर दी है। इससे चीन अंतरिक्ष पर वर्चस्व के मामले में अमेरिका के बराबर आ गया है। लेकिन वाशिंगटन भी इस चुनौती को देखते हुए खामोश नहीं है। अमेरिका ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। उसने चीन को सीमित रखने के प्रयास तेज किए हैं। बाइडेन प्रशासन ने चीनी फर्मों, जैसे हुवावेई और एआई चिप निर्यात पर लगाम लगा कर उसकी तकनीकी प्रगति को सीमित करने के प्रयास किए थे। उभरती तकनीकों में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका यूरोपीय संघ, जापान और भारत से संबंध मजबूत कर रहा है। इसमें 'चिप्स एक्ट' व 'क्वाड' जैसे गठबंधनों ने महत्वपूर्ण तकनीकों तक चीन की पहुंच सीमित करने के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इसके साथ ही ओपेनएआई, गूगल और आईबीएम जैसी कंपनियों को चीनी एआई फर्मों पर बढ़त बनाए रखने के लिए सरकारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि, भारत इस तकनीकी युद्ध में पीछे है, पर वह धीमी गति से बराबरी पर पहुंचने के प्रयास कर रहा है। अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने के साथ ही उसने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है। भारत भी एआई स्टार्टअप तथा क्वांटम कंप्यूटिंग शोध में भारी निवेश कर रहा है। भारत सरकार के 'सेमीकॉन इंडिया इनीशियेटिव' के माध्यम से देश वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्र बनने तथा इंटेल, टीएसएमसी व अन्य कंपनियों से निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में भारत वैश्विक तकनीक परिदृश्य में महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में उभर रहा है। यह दौड़ तेज होने से तकनीक में विश्व व्यवस्था उन तरीकों को परिभाषित करेगी जो इक्कीसवीं शताब्दी को नया स्वरूप देंगे। भारत सरकार इस दौड़ में अनिवासी भारतीयों का पूरा सहयोग ले रही है जो कई विश्वविख्यात टेक कंपनियों के शीर्ष पर हैं।

भारतीय उड्डयन क्षेत्र की प्रगति

भारत का उड्डयन क्षेत्र इस समय महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश की विशाल जनसंख्या तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद उसे हवाईअड्डों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

संतोष मैथ्यू
(लेखक, सहायक प्रोफेसर हैं)

भारत का उड्डयन क्षेत्र इस समय महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश की विशाल जनसंख्या तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद उसे हवाईअड्डों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका में कितने हवाईअड्डे हैं? यह संख्या आपके अधिकाधिक अनुमान से बहुत अधिक यानी लगभग 19,000 है। लगभग 330 मिलियन जनसंख्या वाले अमेरिका ने हवाईअड्डों का व्यापक संजाल बना कर देश भर में सहज कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है।

अब इसकी तुलना भारत से करें। अमेरिका से तीन गुना अधिक जनसंख्या वाले भारत में वर्तमान समय में केवल लगभग 500 हवाईअड्डे हैं। यह तथ्य और भी अधिक आश्चर्यजनक है कि इनमें से केवल 29 को ही अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का दर्जा मिला है। यह भयानक भिन्नता केवल एक आंकड़े से आगे जाती है। इससे भारत के सामने उड्डयन क्षेत्र में ढांचागत चुनौतियां स्पष्ट होती हैं तथा इसके साथ ही इस क्षेत्र के व्यापक विस्तार की आवश्यकता भी उजागर होती है। भारत तथा विदेशों में उड्डयन क्षेत्र की तुलना करने के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के बीच भी तुलना की जा सकती है। दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है पर उनके उड्डयन नेटवर्क में बहुत बड़ा अंतर है।

जहां ब्रिटेन में लगभग 150 हवाईअड्डे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में केवल तीन यात्री हवाईअड्डे-कोलकाता, बागडोगरा और अंडाल हैं। यह अंतर केवल सुविधा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे खोए हुए आर्थिक अवसरों की रूपरेखा स्पष्ट होती है तथा इसके साथ ही तेज ढांचागत विकास की आवश्यकता भी रेखांकित होती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हवाईयात्रा दैनिक सुविधा की चीज है क्योंकि यह सस्ती, सक्षम तथा दैनिक जीवन से जुड़ी है। इससे लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलती है, उनका समय बचता है तथा आर्थिक विकास की गति तेज होती है। लेकिन अब भी भारत में हवाईयात्रा को शानोशौकत की चीज माना जाता है और इसकी पहुंच केवल कुछ विशिष्ट लोगों तक ही है। भारत का उड्डयन नेटवर्क उसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पूरी तरह अपर्याप्त है। केवल 29 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों तथा लगभग कुल 500 हवाईअड्डों के साथ उड्डयन क्षेत्र की ढांचागत संरचना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरू जैसे बड़े शहरों में हवाईअड्डे लगातार भारी भीड़ से भरे रहते हैं जिसके कारण विलंब, भीड़ तथा अक्षमता का सामना करना पड़ता है।

इसके उलट देश के विशाल हिस्से, खासकर छोटे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे से अलगाव का सामना करते हैं और वे रेलवे व राजमार्गों जैसे पुराने परिवहन साधनों पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया-एएआई लगभग 150 हवाईअड्डों का प्रबंधन करती है, लेकिन अमेरिका के लगभग 5000 सिविलियन हवाईअड्डों की तुलना में यह संख्या नाटकीय रूप से नगण्य है। यह अंतर उस समय और भी अधिक चिन्ताजनक हो जाता है, जब यह तथ्य सामने रखा जाता है कि भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है कि भारत को

अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हवाईयात्रा दैनिक सुविधा की चीज है क्योंकि यह सस्ती, सक्षम तथा दैनिक जीवन से जुड़ी है। इससे लोगों को ट्रैफिक समस्या से मुक्ति मिलती है।

अपने उड्डयन ढांचागत संरचना का व्यापक विस्तार करना चाहिए। यह विस्तार तत्काल करने की आवश्यकता है। भारत में सीमित उड्डयन नेटवर्क के भारी नुकसान होते हैं। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सीमित होती है, पर्यटन बढ़ाने में बाधा आती है तथा आर्थिक वृद्धि तेज करने की गति धीमी हो जाती है। भारत को यह कमी दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। भविष्य के लिए साहसी दृष्टिकोण में आने वाले वर्षों में कम से कम 1,500 नए हवाईअड्डे बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बड़े जनसंख्या क्षेत्र में प्रति 100 किलोमीटर पर एक हवाईअड्डा जरूर हो। इस विशाल उड्डयन ढांचागत संरचना का निर्माण कर भारत छोटे शहरों तथा कस्बों की आर्थिक क्षमताओं को विकास का पूरा अवसर दे सकता है। भारत जैसे विशाल देश में सुविकसित हवाई ढांचागत संरचना का विकास और उससे होने वाले आर्थिक लाभ पूरी तरह स्पष्ट हैं। हवाई यात्रा न केवल परिवहन का नवीनतम साधन है, बल्कि यह सर्वाधिक सुरक्षित तथा सर्वाधिक सक्षम है। ऐसे देश में जहां सड़कें और रेलवे अक्सर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण विलंब का शिकार बनते हैं, एक जीवन्त उड्डयन नेटवर्क वर्तमान परिवहन व्यवस्थाओं से बोझ घटा सकता है तथा देश भर में आवागमन को ज्यादा सहज बना सकता है। इसके आर्थिक लाभ भी असाधारण होंगे। हवाईअड्डों की संख्या में वृद्धि से हजारों रोजगारों का सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से बिजनेस गतिविधियां बढ़ेंगी, पर्यटकों की यात्रा आसान होगी तथा आम जनसंख्या को भी समय खर्च करने वाली सड़क व रेल यात्राओं का विकल्प मिलेगा। हालांकि, नए हवाईअड्डों के विकास के लिए भारी निवेश और समय की जरूरत होगी, पर भारत में खोजी समाधान निकालने की क्षमता है।

ऐसा एक दृष्टिकोण राजमार्गों को आपातकालीन रनवे में बदलना है। इस माडल का अमेरिका में सफल क्रियान्वयन हुआ है। भारत में राजमार्गों के परिवर्तन में इस अवधारणा का व्यापक प्रयोग हो सकता है। इससे छोटे विमान दुर्गम क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकते हैं और इसमें पूरी तरह नए हवाईअड्डे बनाने पर होने वाला खर्च भी बचेगा।

पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह रणनीति गेमचेंजर हो सकती है। रोड-रनवे हवाई कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में लागत-प्रभावी विकल्प हो सकते हैं, इससे दैनिक यात्रियों को लाभ होगा तथा प्राकृतिक आपदा जैसे संकटों के समय आपातकालीन सेवाओं को लाभ मिलेगा। पश्चिमी देशों में हवाई यात्रा का विकास दैनिक जीवन के अंग के रूप में हुआ है। यह सस्ती, सक्षम तथा व्यापक पहुंच में है। लेकिन भारत में हवाईयात्रा अब भी शानोशौकत की चीज मानी जाती है जो औसत नागरिक की पहुंच से बाहर है।

यह दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले बहुत बड़े देश में हवाई यात्रा एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे सभी आर्थिक स्तर वाले लोगों को लाभ मिलना चाहिए। उड्डयन नेटवर्क के विस्तार से उड़ानें जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए ज्यादा सस्ती और व्यावहारिक हो जाएंगी। भारत उड्डयन यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश की आर्थिक प्रगति तथा विशाल जनसंख्या के लिए समान रूप से तेज हवाई यात्रा ढांचे का विस्तार जरूरी है। 'उड़ान' योजना जैसी सरकारी पहलों का लक्ष्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। निकट भविष्य में कम से कम 1,500 हवाईअड्डे विकसित करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि हर क्षेत्र, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे अविकसित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। हाईवे-रनवे जैसे खोजी विचारों से हवाई यात्रा ज्यादा सस्ती होगी तथा भारत में उड्डयन कमी दूर करने की दिशा में हवाई पट्टियों के विस्तार में योगदान मिलेगा। भारत में एक जीवन्त उड्डयन ढांचागत संरचना का तत्काल विकास आवश्यक है और इस पर फौरन काम शुरू किया जाना चाहिए।

प्रेम और मुक्ति का दैवीय संयोजन

"पृथ्वी पर कहीं और ऐसा नहीं है कि लाखों-करोड़ों लोग, अटूट समर्पण के साथ, ईश्वर के नाम का जाप करते हुए, दिन-रात साधना में लीन होकर एकत्रित होते हैं।"

साईं मां लक्ष्मी देवी
(लेखिका, आध्यात्मिक गुरु हैं)

सदियों से महान गुरु कुंभ मेले की ओर आकर्षित होते रहे हैं, इसके आध्यात्मिक आकर्षण से मोहित होते रहे हैं। वह क्या है जो हमें यहां खींचता है? यह भक्ति की गहन ऊर्जा है, दिव्य प्रेम की अदम्य शक्ति है। प्रेम अपने आप में एक चुंबक है, और जो लोग भक्ति में रहते हैं, वे इस चुंबकीय शक्ति को विकीर्ण करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी पर कहीं और ऐसा नहीं है कि लाखों-करोड़ों लोग, अटूट समर्पण के साथ, ईश्वर के नाम का जाप करते हुए, दिन-रात साधना में लीन होकर एकत्रित होते हैं।

वे इस पवित्र ऊर्जा में स्नान करने आते हैं और इसे अपने जीवन में आगे ले जाते हैं, जहां भी जाते हैं, इसकी चमक फैलाते हैं।

यह महाकुंभ पहले के किसी भी कुंभ से अलग है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है। यह वैश्विक महत्व की एक आध्यात्मिक घटना है, जहां स्रोत ऊर्जा की उच्चतम आवृत्तियाँ मानवता पर उतरती हैं। ज्ञान की कृपा प्रदान की जा रही है, और आत्माओं का जागरण हो रहा है।

यहां, सोरूबा समाधि की उदात्त अवस्था शुरू होगी - एक ऐसा परिवर्तन जो चेतना और पदार्थ दोनों को ऊपर उठाता है। कोशिकीय संरचनाओं का पुनर्जनन हो रहा है, जो मानव डीएनए को दिव्य छाप से जोड़ रही है, हमें भीतर के अमर तत्व से जोड़ रही हैं। कुंभ के अनुभव जैसा कुछ भी नहीं है। कल्पना करें कि लाखों आत्माएं एक स्थान पर एकत्रित हो रही हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण कर रही है, जिससे शक्ति का एक विशाल भंवर बन रहा है। इस पवित्र स्थान पर, हम

अपनी मानवीय पहचानों से ऊपर उठ जाते हैं और खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं - एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में एकजुट शुद्ध आत्माएँ। यह सामूहिक ऊर्जा प्रेम, प्रकाश और ज्ञान की शक्ति है, जो कर्म के बोझ को खत्म करती है और एक राजसी, दिव्य जीवन का मार्ग खोलती है। यद्यपि वर्तमान युग अपनी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ रहते हैं, वे गहन परिवर्तन से गुजरेंगे। ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं, जो मुक्ति और जागृति प्रदान करते हैं। हम जो दुनिया देखते हैं वह एक भ्रम है - माया का एक खेल - जहाँ ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को छोड़कर सब कुछ क्षणभंगुर है। यह प्रेम हमारा धर्म है, हमारा अंतिम उद्देश्य है। शरीर, मन और भौतिक दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन शाश्वत सत्य, सत्य, अपरिवर्तित रहता है। हम वह सत्य हैं- सत्-चित्-आनंद, तत् त्वम् असि- और हमारी साधना इस अनुभूति को जागृत करना और उसे मूर्त रूप देना है।

कुंभ में, माता गंगा की गोद में, हम समर्पण करते हैं और रूपांतरित होते हैं। पवित्र जल हमें शुद्ध करता है, हमारे भीतर दिव्य रूपरेखा को सक्रिय करता है। इस शक्तिशाली भंवर में, हम सनातन धर्म की उच्चतम अभिव्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं, गहन आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव करते हैं। इस वर्ष, दिव्य प्रकाश का प्रवाह अपार है, जो हमें इसकी असीम चमक और आनंद के साथ विलीन होने के लिए आमंत्रित करता है। मोक्ष और ज्ञान की प्राचीन परंपराएं पहले से कहीं अधिक जीवंत हैं। यह शुद्धि का समय है, आसक्ति और नश्वरता के भ्रम को छोड़ने का। निस्वार्थ सेवा पर आधारित सनातन धर्म का उदाहरण आदि शंकराचार्य ने दिया, जिन्होंने एकता का ज्ञान सिखाया।

धर्म- शाश्वत नियम- सृष्टि को बनाए रखता है। चाहे कितने भी धार्मिक मार्ग हों, सभी इस सार्वभौमिक सत्य से निकले हैं। हमने अनगिनत जन्मों से धर्म का पालन किया है, चाहे हमें यह याद हो या न हो। कुंभ मेला आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, जो दुनिया भर से साधकों को आकर्षित करता है।

यहां तक कि उन देशों से भी जहां भक्ति दुर्लभ है, वे भी गहन बदलावों से गुजरते हैं, उनके मन को शांति मिलती है और उनके दिल खिल उठते हैं। यहां, लाखों लोग एक साथ मंत्रोच्चार करते हैं, और दिव्य शक्तियां सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए काम करती हैं। यह महान आध्यात्मिक क्रांति का समय है, जो सत्य युग की सुबह की घोषणा करता है। अपना दिल खोलो। अपनी आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करो। अपने सत्य में कदम रखो और उस नए युग को अपनाओ जो हमारे सामने है।

आप की बात

व्यवस्थाएं दोषी

अनहोनियां होती आई हैं, और संभवत: होती भी रहेंगी। इन्हें रोकना तभी संभव है जब हर वाहन चालक हमेशा परिचालन के प्रति सजग व सिंसीयर रहे. दूसरे हादसे जो होते हैं अगर वे प्राकृतिक कारणों से होते हैं तो उनपर तो किसी का जोर नहीं किन्तु व्यवस्थाओं की लापरवाहियों के कारण जो हादसे होते हैं तब तो दोषी व्यवस्थाएं ही मानी जाएंगी. फिर चाहे वे छोटे हों या बड़े. वाहन का चालक भी सरकारी, गैरसरकारी, व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था का हिस्सा होता है और छोटे-बड़े आयोजनों के आयोजक भी व्यवस्थापक होते हैं. फिर वे चाहे राजनीतिक हों या, सामाजिक अथवा धार्मिक. अगर आयोजन कर्ता/व्यवस्थापक सुचारु व्यवस्था करने में असमर्थ है तो उसे आयोजनों से दूर ही रहना चाहिए, परन्तु कुछ आयोजन फिर चाहे वे त्यौहारी हों या किसी भी तरह के सामाजिक जिसकी व्यवस्था आयोजक और शासन/प्रशासन को मिलकर करना जरुरी होता है तब उसे अपनी ड्यूटी योजनाबद्ध तरीके व ईमानदारी से निभानी चाहिए, अगर वे अपनी ड्यूटी के प्रति जवाबदेह रहेंगे और प्रीप्लानिंग से कार्य करेंगे तो अवश्य कसी भी तरह के हर हादसों पर नियंत्रण रह सकता है. हमारे यहां एक सबसे बड़ा ड्राबैक है कि जहां भी फिर वो सामाजिक काम हो, या राजनीतिक अथवा धार्मिक अगर थोड़ी सी भी लोगों की भीड़/हुजूम आदि इकट्ठा होता है तो वीवीआईपी वहां दौड़े चले आते हैं।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

क्या है बजट में?

केन्द्रीय बजट में 12 लाख तक की आय को करमुक्त करना ना निश्चित ही भारत के माध्यम आय वर्ग के लिए आह्लादकारी है और इस घोषणा का सर्वत्र स्वागत हुआ है परन्तु जनतांत्रिक व्यवस्था में क्या निजी आय पर कर अनुचित नहीं? राजकोष को बढ़ाने के अन्य अनेक साधन हो सकते हैं किन्तु सब के प्रति समानता का व्यवहार जनसामान्य को स्वेच्छा से भी राजकोष की दृढ़ता के प्रति उत्तरदायी बना सकता है जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर पर सरकारी अनुदान छोड़ दिया था । सम्पूर्ण भारत में सभी प्रकार की सरकारी ऋणमुक्ति पर प्रतिबन्ध हो, किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार से नकद राशि देना अथवा किसी राजनीतिक दल द्वारा ऐसा करने का आश्वासन बन्द हो। जाति पंथ आधारित विद्यार्थियों को कोई धनराशि देना बन्द हो, जनकल्याण के नाम पर जनसुविधाओं को (जिनके उत्पादन में श्रम और धन का व्यय हुआ) मुफ्त देना बन्द हो । जीवन के लिए आवश्यक अनाज, चावल, दालें, नमक, चीनी, आलू, प्याज, खाने का तेल आदि पदार्थों के मूल्यों में बी पी एल के लिए अनुदान की अपेक्षा उसी अनुदान से सभी को ये पदार्थ कम मूल्य पर मिलें । छात्रवृत्ति का लाभ केवल मेधावी छात्रों के लिए हो न कि जाति पंथ आधारित। देश के युवा को उद्यमी बना कर उसके रोजगार की व्यवस्था करना ठीक होगा न कि उसे मुफ्त की आदत डालना।

– **जय प्रकाश गुप्ता**, अंबाला छावनी

अमेरिकी टैरिफ नीति

हाल ही में अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम अमेरिका की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अमेरिकी दृष्टिकोण से यह नीति उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, घरेलू रोजगार के अवसर बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास है। इससे अमेरिका में स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता को बल मिलेगा। भारत के लिए यह स्थिति नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका के लिए भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। विशेष रूप से टेक्सटाइल, आईटी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को निर्यात में बढ़त मिलने की संभावना है। इसके अलावा, यह निर्णय भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी समर्थन दे सकता है। भारत यदि अपनी विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत करता है, तो वह अमेरिका के लिए चीन का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। यह स्थिति भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बना सकती है। अत: अमेरिका की यह नीति भले ही कुछ देशों के लिए चुनौती हो, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह नए-नए अवसर प्रदान कर सकती है।

– **आर के जैन**, बड़वानी, मप्र

डूबती नैया के संकेत

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत लायक वोट होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी की जीत का नतीजा कांग्रेस-आप गठबंधन के लिए गहरी चिंता पैदा कर गया है, खासकर तब जब दिल्ली एक सप्ताह में अपना भाग्य तय करने वाली है। कुल 36 में से सभी वोट वैध होने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत बबल को गठबंधन के दो सदस्यों का समर्थन मिलना नई राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए काफी है। इस हार के मायने स्थानीय स्तर तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के भीतर अब तक असंतोष और अस्थिरता के संकेत भी है। चंडीगढ़ की हार गठबंधन में अंदर ही अंदर चल रही राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लहर के उछाल के भी संकेत है।इस हार को महज क्रॉस वोटिंग का नतीजा ही समझा जाए या गठबंधन के भीतर बढ़ते असहमति का संकेत? क्या यह कांग्रेस और आप के कार्यकर्ताओं में विश्वास की कमी नहीं दर्शाता है? या फिर भाजपा की रणनीतिक बढ़त का प्रमाण है? चूंकि चंडीगढ़ की हार स्थानीय मुद्दा है फिर भी दिल्ली चुनावों में आप-कांग्रेस दोनों भाजपा को हराने के लिए प्रयासरत है ऐसे में उनका आंतरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

श्रद्धा स्वत :स्फूर्त होती है जो अंत :करण से उपजती है

ट्रंप का टैरिफ वार

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू कर दिया। उन्होंने पहले दी गई अपनी चेतावनी के अनुसार कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयातित सामग्री पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। जहां कनाडा और मेक्सिको पर 25-25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया वहीं चीन पर 10 प्रतिशत। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कनाडा और मेक्सिको की तुलना में चीन पर कुछ नरमी बरती। यह नरमी इसलिए एक पहेली जैसी है कि चीन तो अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा है और उसके वर्चस्व को कम करना चाहता है वहीं कनाडा और मेक्सिको अमेरिका के पड़ोसी हैं। इनमें भी कनाडा अमेरिका का खास सहयोगी रहा है। स्पष्ट है कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने अभियान के तहत निकटतम सहयोगियों पर भी कोई कृपा दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन इसमें संदेह है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया है, उससे अमेरिका को लाभ ही लाभ होगा। पूरे आसार हैं कि इससे अमेरिका को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब कनाडा, मेक्सिको और चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा और इसके दुष्परिणाम अमेरिकी जनता को भोगने पड़ेंगे।

आश्चर्य नहीं कि ट्रंप के फैसले के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया और मेक्सिको तथा चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करने की घोषणा की है। हो सकता है कि आगे चलकर अमेरिकी राष्ट्रपति इन तीनों देशों से अपने मन-मुताबिक समझौते करने में सफल हो जाएं, लेकिन भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वह भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं। पिछले दिनों बजट के जरिये वित्त मंत्री ने आयातित मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर आयात शुल्क घटाया है, लेकिन देखना यह है कि ट्रंप इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं। चूंकि अगले कुछ दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा संभावित है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि दोनों देश बातचीत के जरिये किसी सहमति पर पहुंचने में समर्थ होंगे। यदि भारत और अमेरिका के बीच आयात शुल्क को लेकर कोई सहमति बन जाती है तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा। भारत की कोशिश बातचीत के जरिये समस्या के समाधान की होनी चाहिए, लेकिन बात तब बनेगी जब ट्रंप यह समझेंगे कि वह अमेरिका को आगे रखने के फेर में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही विश्व व्यापार में असंतुलन पैदा करने का ही काम करेंगे। अमेरिका एक प्रभावशाली राष्ट्र है और यदि वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है तो उसे एक जिम्मेदार देश की भूमिका का निर्वाह करना होगा। फिलहाल तो ट्रंप अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि वह यह चाह रहे हैं कि अमेरिका डालर के प्रभुत्व का लाभ उठाता रहे और फिर भी अन्य देश अपने व्यापारिक हितों की चिंता न करें तो यह संभव नहीं।

विकास को गति

केंद्रीय बजट में जो प्रविधान किए गए हैं, उससे बिहार के विकास को और गति मिल सकेगी। अब इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए इस अवसर का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है। मखाना यहां के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है, जिससे हजारों परिवार जुड़े हैं। देश का 90 प्रतिशत मखाना बिहार ही देता है। मखाना का निर्यात कई अन्य देशों को भी किया जाता है। शोध-अनुसंधान के साथ मखाना उत्पाद को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पहले से कार्य कर रही है। अब केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे इसे और अधिक बल मिलेगा। राज्य को अपने संसाधन का उपयोग करते हुए आय के स्रोत बढ़ाने होंगे, ताकि लोगों को रोजगार के साथ समृद्धि बढ़े। कृषि यहां का मूल ढांचा है, जिस पर यहां की अर्थव्यवस्था टिकी है। इसे बाजार की मांग के अनुरूप बढ़ाना ही समय की मांग है। ऐसे में मखाना बोर्ड जैसी संस्था इसमें बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। मुख्य रूप से कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मखाना उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। अभी प्रदेश में मखाना का लगभग पांच सौ करोड़ का कारोबार है। बोर्ड के गठन के बाद सुविधा भी बढ़ेगी और आधारभूत संरचना भी मजबूत होगी। इससे बाजार के करीब तीन हजार करोड़ तक पहुंचने की आशा की जा सकती है। इसी तरह पर्यटन क्षेत्र में भी बिहार को लाभ हो सकता है, क्योंकि यहां ऐसे स्थलों की भरमार है। वैसे यदि धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों की पहचान करते हुए उन्हें सही से विकसित किया जाए तो बिहार में पर्यटन की संभावना व्यापक है।

> बजट की घोषणाओं के बाद अब जरूरत इस बात की है कि नए लक्ष्य के साथ सब मिलकर आगे बढ़ें

जारी रहे सुधारों का सिलसिला

आदित्य सिन्हा

अच्छी बात है कि बजट में सुधारों पर जोर दिया गया है, लेकिन आर्थिक संभावनाओं को व्यापक रूप से भुनाने के लिए भविष्य में और सुधार करने होंगे

यह पिछली सदी के अंतिम दौर की बात है जब जर्मनी को 'सिक मैन आफ यूरोप' कहा जाने लगा था। जर्मनी जैसा देश ऐसे ही यूरोप की कमजोर कड़ी नहीं बन गया था। अर्थव्यवस्था में ठहराव, ऊंची बेरोजगारी और अड़ियल श्रम कानूनों ने वृद्धि की राह रोक दी थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर ने हाट्र्ज सुधारों का सूत्रपात किया। इनके जरिये जिन श्रम सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप को सुधारा गया, उन्होंने जर्मन अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। जैसा कि प्रत्येक सुधारों के साथ होता है, आरंभ में उनका भी विरोध हुआ। हालांकि इन सुधारों ने जर्मन श्रम बाजार की क्षमताओं को बेहतर बनाया। रोजगार के अवसर बढ़ाए और जर्मनी को यूरोप की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रसंग का यही सार है कि जब साहसिक सुधारों को सही तरह से लागू किया जाता है तो उसके दूरगामी एवं दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार के बजट में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जो बजट प्रस्तुत किया, वह क्षमताओं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ ही राजकोषीय अनुशासन के प्रति समर्पित है। बजट में कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय ढांचे से जुड़े जिन सुधारों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, उनसे नई उम्मीदें जगती हैं। इन सुधारों का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि की राह में अवरोधों को दूर कर क्षमताओं को बढ़ाना है। इससे निवेश आकर्षित होगा। शासन संचालन का ढांचा सुसंगत बनेगा। परिणामस्वरूप तेज आर्थिक वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां आकार लेंगी। टैक्सेशन यानी कराधान इन सुधारों के केंद्र में है। पिछले कुछ वर्षों से कर अनुपालन के मोर्चे पर आई व्यापक सहजता को नए क्षितिज पर ले जाने के लिए सरकार तत्पर दिखती है। इसी कड़ी में जल्द ही न्यू टैक्स बिल पेश किए जाने की तैयारी है। दशकों से ऐसे सुधार की प्रतीक्षा रही है। इसका उद्देश्य करों से जुड़े विवादों को घटाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड फिलहाल कर विवाद से जुड़े 60,000 मामलों में उलझा हुआ है। ऐसे में कर अनुपालन व्यवस्था को और सुगम बनाना कई स्तरों पर लाभदायक होगा। इससे करदाता और प्राधिकारी संस्थाओं दोनों के लिए आसानी होगी। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी के स्तर पर भी विविधीकृत दरें उसे उलझाऊ बनाती हैं, लेकिन उसे सुलझाने के लिए जीएसटी परिषद में राज्यों को भी साधना होगा। कर ढांचे को सुसंगत बनाने से नागरिकों व उद्यमों का भरोसा बढ़ेगा एवं आर्थिक वृद्धि को तेजी के पंख लगेंगे।

अरविंद राणा

बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रविधान है, लेकिन यह केवल उन्हीं कंपनियों के लिए अनुमन्य होगा जो एकत्रित प्रीमियम की पूरी राशि को भारत में ही पुनः निवेश करेंगी। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के साथ ही बीमा की पैठ भी गहरी होगी। हालांकि इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर होगी कि इस पहल को किस प्रकार अमल में लाया जाता है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क से स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ेगा। वित्तीय संसाधनों तक इन समूहों की पहुंच बढ़ेगी। सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कमान संभाले तो उसकी राह में संभावित बाधाओं को दूर करने के प्रयत्नों की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। बजट में गैर-वित्तीय क्षेत्रों के नियमन, प्रमाणन और लाइसेंस की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का प्रविधान है, जो साल भर के भीतर मामलों को निपटाएगी। विश्वास आधारित यह पहल अनावश्यक अनुपालन बोझ घटाएगी। राज्यों को भी इस मामले में अंशभागी बनाने और प्रोत्साहन के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा। इससे सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा, शहरी विकास और खनन क्षेत्र में भी बजट ऐसे सुधारों को लक्षित करता है जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक बनेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार अक्षय ऊर्जा अपनाने की राह आसान बनाएंगे। इनसे ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा और बिजली वितरण नियमन सुसंगत बनेंगे। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए भरोसेमंद बिजली आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तीय बोझ से कराह रहीं बिजली वितरण कंपनियों यानी डिसकाम के इलाज का कोई नुस्खा नहीं तैयार हुआ है। इन कंपनियों के लिए सुधारों की गुंजाइश अभी बनी हुई है जो टैरिफ को तार्किक बनाने के साथ कंपनियों के वित्तीय ढांचे को दुरुस्त बना सकें। शहरी विकास को लेकर किफायती आवास, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर है। हालांकि स्थानीय निकायों की दुर्दशा एवं उनमें वित्तीय अनियमितता और भूसंपदा उपयोग जैसे पहलू अभी भी चुनौती बने हुए हैं। खनन सुधारों का जोर पारदर्शिता बढ़ाने पर है। इससे नीलामी प्रक्रिया में सुधार के साथ निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन परिवर्तनों से उन महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ेगी जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, मगर इसमें सफलता इसी पर निर्भर होगी कि खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय मानकों में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाता है।

अच्छी बात है कि बजट में सुधारों पर जोर दिया गया है, लेकिन भविष्य में और सुधार करने होंगे। निवेश अनुकूल परिवेश बनाने के लिए यह आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय ढांचे में स्पष्टता, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ाव का ध्यान रखना होगा। बजट में प्रस्तावित सुधारों को यदि क्रियान्वित किया जा सका तो अगले एक दशक के दौरान देश तेज आर्थिक वृद्धि का साक्षी बनेगा और विकसित भारत का लक्ष्य निकट आता जाएगा।

(लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

दिल्ली में सत्ता की कुंजी कांग्रेस के हाथ

राज कुमार सिंह

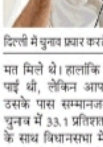

आप का विजय रथ दिल्ली में तभी रुक सकता है, जब कांग्रेस अपना मत प्रतिशत 4.3 से बढ़ा कर तीन गुणा तक ले जाए

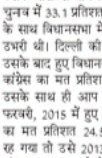

चुनावी राजनीति का खेल भी अजीब है। दो दावेदारों के बीच सत्ता की जंग में हार-जीत का फैसला कई बार तीसरे खिलाड़ी के खेल पर निर्भर करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही समीकरण बनता दिख रहा है। दिल्ली अधूरा राज्य है, जिसकी सत्ता के कुछ निर्णायक सूत्र उपराज्यपाल के जरिये केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। फिर भी अधूरे राज्य की सत्ता की जंग पूरे जोर-शोर से लड़ी जा रही है। इस जंग में चुनावी वादों से लेकर दलगत और निजी आरोप-प्रत्यारोप तक के इस्तेमाल से कोई परहेज नहीं दिख रहा। आप दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो 70 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र आठ सीटों के साथ भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। सत्ता की जंग इन दोनों के बीच ही मानी जा रही है, फिर भी कांग्रेस चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाती दिख रही है।

पहले जनसंघ और फिर भाजपा ही दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी खिलाड़ी रही। परिदृश्य बदला 2013 के विधानसभा चुनाव में। तत्कालीन संप्रग सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के चर्चित आंदोलन के बाद उन्हीं के कुछ शिष्यों द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई गई आम आदमी पार्टी यानी आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी और 15 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल कर 28 सीटों के साथ दूसरा बड़ा दल बन गई। सबसे बड़ा दल भाजपा थी 31 सीटों के साथ, पर उसे सत्ता से रोकने की खातिर कांग्रेस ने उसी आप की सरकार अपने समर्थन से बनवा दी, जिसने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया था। क्या कांग्रेस का वह फैसला दिल्ली में आत्मघाती साबित हुआ? इस सवाल के जवाब में उसकी संभावित चुनावी भूमिका का संकेत भी छिपा है। इसे समझने के लिए 2013 और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में इन तीनों राजनीतिक दलों को मिले मतों का प्रतिशत जानना और उसे समझना जरूरी है।

अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 2013 में जब आप ने 29 प्रतिशत मत हासिल करते हुए 28 सीटें जीती थीं, तब भी कांग्रेस को 24.5 प्रतिशत मत मिले थे। हालांकि कांग्रेस मात्र आठ सीटें जीत पाई थी, लेकिन आप द्वारा सेंधमारी के बावजूद उसके पास सम्मानजनक मत प्रतिशत था। उसी चुनाव में 33.1 प्रतिशत मत लेकर भाजपा 31 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में हुआ, जिनमें कांग्रेस का मत प्रतिशत लगातार गिरता गया और उसके साथ ही आप का ग्राफ चढ़ता गया। यदि फरवरी, 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 24.5 से गिर कर 9.7 प्रतिशत रह गया तो उसे 2013 में अपने समर्थन से आप की सरकार बनवाने के अलावा किस राजनीतिक भूल का परिणाम माना जा सकता है? 2015 के विधानसभा चुनाव में आप का मत प्रतिशत 29 से छलांग लगाकर 54.6 प्रतिशत पर पहुंच गया। दरअसल आप ने कांग्रेस से उसका परंपरागत वोट बैंक गरीब, दलित और अल्पसंख्यक छीनते हुए भाजपा के मिडिल क्लास वोट बैंक में भी सेंध लगाई। भाजपा का मत प्रतिशत 33.1 से गिर 32.2 प्रतिशत पर आ गया। इसका अंतिम चुनावी परिणाम यह निकला कि 28 सीटों वाली आप ने 67 सीटों के साथ इतिहास रच दिया तो 31 सीटों के साथ पिछली विधानसभा में सबसे बड़ा दल रही भाजपा तीन सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2020 के चुनाव में भी आप की कमोबेश वैसी ही चुनावी सफलता ने उसके पंखों को इतनी ऊंची उड़ान दे दी कि वह 2022 में पंजाब में भी सत्तारूढ़ हो गई तथा गुजरात और गोवा में मिले मत प्रतिशत और सीटों के बल पर राष्ट्रीय दल का दर्जा पा गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अपना मत प्रतिशत 32.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 38.5 तक ले जाने के बावजूद आप का 62 सीटें जीत जाना चौंकाने वाला रहा। बेशक सीटें भाजपा की भी तीन से बढ़ कर आठ हो गईं, पर कांग्रेस का मत प्रतिशत और भी आधा रह जाने के चलते आप अपने मत प्रतिशत में एक प्रतिशत की गिरावट के बावजूद लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत पाने में सफल रही। कांग्रेस का मत प्रतिशत 9.7 से गिर कर 4.3 रह गया, जबकि आप का मत प्रतिशत 54.6 से गिर कर 53.6 प्रतिशत हो गया। इसलिए यदि पांच फरवरी को होने जा रहे चुनाव में भाजपा पिछली बार की तरह इस बार भी अपना मत प्रतिशत चार या पांच प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, तब भी वह आप को बहुमत पाने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इसके बावजूद आप 47-48 प्रतिशत मतों के साथ भाजपा से आगे रहेगी।

दिल्ली में चुनाव प्रचार करते राहुल गांधी । फाइल

ऐसे में आप का विजय रथ दिल्ली में तभी रुक सकता है, जब कांग्रेस अपना मत प्रतिशत 4.3 से बढ़ा कर तीन गुणा तक ले जाए। अगर कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा ले तो आप का मत प्रतिशत गिर कर भाजपा के संभावित मत प्रतिशत से भी नीचे जा सकता है और दिल्ली में सत्ता की बाजी पलट सकती है। इस तरह त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे कमजोर होते हुए भी सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका कांग्रेस निभा सकती है। अगर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता का कमल खिला तो उसमें अप्रत्यक्ष भूमिका हाथ की भी रहेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संतोष सुख

आज हम भोगवादी सभ्यता में जी रहे हैं। हर कोई नाना प्रकार की सुविधाएं चाहता है। धन चाहता है। वैभव की आकांक्षा करता है और क्षणिक सुख के पीछे दौड़ता है। इसी तरह मन भी बेकाबू होकर छलांग लगाता है। वह भांति-भांति की वस्तुओं की ओर ललचाता है। यही स्थिति दुख का कारण बनती है। इसी से असंतोष और तनाव पनपता है। डायोजनीज के लिए एक कोना भी बहुत है, परंतु सिकंदर के लिए पूरा संसार भी छोटा है। डायोजनीज संतोष का प्रतीक है। सिकंदर लोभ का प्रतीक है। एक छोटी सी कुटिया भी डायोजनीज के लिए बहुत बड़ी थी। वह उसी में आनंदित था। वहीं, सिकंदर सम्राट होकर भी असंतुष्ट था। वह चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर शासन करूं कि सारे संसार पर मेरा आदेश चले।

क्या सुखी होने के लिए सारे संसार पर अपना आदेश चलाना जरूरी है? सुख की ऐसी शर्त नहीं है। हां, लोभ की ऐसी शर्त अवश्य है। लोभ जरूर कहता है कि पहले संसार को जीतो, तब सुख मिलेगा। जबकि सच यह है कि तब भी सुख नहीं मिल पाता है। गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद-ये सभी हमारे आचरण से पतझड़ के पत्तों की भांति झड़ गए हैं। हृदय से मानवीय-प्रेम या करुणा का संवेदनशील स्वर, मस्तिष्क से नैतिक चिंतन की अवधारणा और नाभि से उद्भूत संयम और सम्यक आचरण का संकल्प कहीं खो गया है।

आवश्यकता शरीर की तृप्ति चाहती है तो वासना अहंकार की तृप्ति में ही लगी रहती है। अहंकार तो कभी किसी का तृप्त हुआ ही नहीं है। सुंदर सोच से ही संतोष का जन्म होता है जो आपको जहां है और जैसे हैं, वहीं राजा बना देता है। संतोष से सुख नहीं उपजता, बल्कि संतोष स्वयं सुख है। संतोष स्वयं एक परितृप्ति है। एक अमृत की रसधार है वह। उसका रसपान कीजिए।

ललित गर्ग

प्लास्टिक कचरे का बढ़ता खतरा

धैंर्यराज सुथार

> तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में प्लास्टिक कचरे का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए

थाइलैंड ने विकसित देशों से प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट और अधिक गंभीर हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश वर्षों से अपने प्लास्टिक कचरे को थाइलैंड भेजते रहे हैं, जिसे 'अपशिष्ट उपनिवेशवाद' कहा जाता है। हालांकि, इससे थाइलैंड को कुछ आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसके बदले में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ीं। इसी कारण एक जनवरी 2025 से थाइलैंड ने प्लास्टिक कचरे के आयात को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है।

भारत में भी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन चुनौती बना हुआ है। हालांकि, 2018 में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद गैरकानूनी रूप से यह प्रक्रिया जारी है। भारत में पहले से ही घरेलू प्लास्टिक कचरे की मात्रा अत्यधिक है और इस अतिरिक्त कचरे के कारण समस्या और विकराल हो जाती है। भारत में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते आयात और प्रबंधन की समस्या से कई नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। यह पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान की कमी से जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण बढ़ता है। खुले में जलाने से हानिकारक रसायन और विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्लास्टिक कचरा नदियों और समुद्रों में बहकर जलीय जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखा जाता है। प्लास्टिक कचरे से निकलने वाले सूक्ष्म कण हवा और पानी में मिलकर लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियां, त्वचा रोग और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से भारत में अनौपचारिक कचरा बीनने वाले समुदायों को इससे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वे बिना किसी सुरक्षा उपायों के इस कचरे को संभालते हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत स्रोत पर ही कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाया गया। वर्ष 2021 के संशोधन में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया।

हालांकि, इस तरह के तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या गंभीर बनी हुई है। कड़े नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। साथ ही प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देना और जनसहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यदि भारत इस दिशा में प्रभावी कदम उठाता है, तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सुधारनी होगी शहरों की दशा

'निराश करती नगरीय शासन व्यवस्था' शीर्षक से लिखे आलेख में संतोष नारगुंड एवं मानसी वर्मा ने दिल्ली की नगरीय शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि दिल्ली में मेयर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इस कारण भी दिल्ली में अनेक कुव्यवस्था देखने को मिलती हैं। इसका असर देश की छवि पर पड़ता है, क्योंकि देश की राजधानी होने के नाते विश्व भर के देशों की निगाहें इस शहर पर रहती हैं। वैसे भी अर्थव्यवस्था को बल शहरी क्षेत्र से मिलता है। हालांकि हमारे शहरों की खस्ताहाल व्यवस्था के लिए नगर निकायों की खराब कार्यप्रणाली भी जिम्मेदार है। कई बार राज्य, केंद्र व नगर निगम के बीच विकास एवं प्रशासन संबंधित टकराव देखने को मिलते हैं। केंद्र में अभी मजबूत सरकार है तो देश को उम्मीद है कि केंद्र व्यापक बदलाव वाला कोई कदम उठाएगा। ऐसा कदम जो राज्य, केंद्र व नगर निगम की जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन करे और उत्तरदायित्व तय किए जा सकें।

मुकेश कुमार मनन, पटना

जनहित व समृद्धि का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। केंद्र सरकार ने इस मानस से यह महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है कि मध्य वर्ग राष्ट्र निर्माण के निमित्त आहूत है। इसलिए विराट हृदय से आय कर में भारी छूट, एमएसएमई, किसान, उद्योग व्यापार और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी राहत के साथ भारी निवेश का प्रविधान किया है। अगले सप्ताह नया आयकर बिल संसद में अपेक्षित है, जिससे इस बजट के अनुरूप संस्थागत संशोधन और उद्योग-व्यापार में सरलीकरण के प्रविधान लाए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने आम आदमी और मध्य वर्ग के जीवन के हर पक्ष को छुआ है। जिससे उसके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त हो। इसका प्रभाव दो वर्षों में देश की बड़ी आर्थिक वृद्धि में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि रक्षा के लिए किसी भी खर्च और निवेश में कमी नहीं होने दी जाएगी। पड़ोसी देश चीन ने रक्षा में भारतीय मुद्रा के सापेक्ष 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा में बजटीय प्रविधान में हम चीन के एक तिहाई निवेश पर ही हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने राजस्व संग्रहण का पांच प्रतिशत रक्षा के लिए सुरक्षित रखें। शिक्षा के लिए भी 1,28,650 करोड़ का आवंटन अपर्याप्त है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है इसलिए राज्य सरकारों को भी शिक्षा के लिए अपने बजटों में अपनी सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत आवंटन तो करना ही चाहिए, तभी केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए वित्तीय पोषण कर सकते हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

मेलबाक्स

आर्थिक चुनौतियां

रविवार को प्रकाशित संजय गुप्त ने अपने आलेख 'आसान नहीं आर्थिक चुनौतियों से पार पाना' में सरकार के संज्ञान में यह बातें लाई हैं कि आम बजट 2025-26 में बजट से पहले आए आर्थिक सर्वे की जरूरी बातों को दरकिनार कर दिया गया है। इन रिपोर्टों में स्वास्थ्य, बिजली, श्रम, बाजार, नगर निकायों आदि मुद्दों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह मध्य वर्ग की उम्मीदों का बजट है। मध्य वर्ग और नौकरी पेशा समुदाय के लिए आज बजट से जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि एक कमाईशुदा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। यानी हर महीने आपकी एक लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबका विकास लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट की थीम के अनुरूप, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। सबका विकास थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है।

-युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

15 करोड़ डीमैट खाते हो गए हैं भारत में। इतना ही नहीं, लगभग 45 करोड़ भारतीय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयर बाजार से जुड़ चुके हैं। ऐसे में शेयर बाजार को भी केंद्रीय बजट से आशाएं बढ़ गई हैं।

आजकल

वैश्विक षड्यंत्र पर अस्थायी ब्रेक

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

संसद के बजट सत्र आरंभ होने के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण का आरंभ समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की प्रार्थना के साथ किया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद यह संसद का पहला सत्र है जिसके पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। विदेश से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जब ऐसा कह रहे हैं तो यह अकारण नहीं है। भारत विरोधी माहौल बनाने में विदेश से सक्रिय संगठनों और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स की भी बड़ी भूमिका देखी गई है

बजट सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र आरंभ होने के पहले अपने पारंपरिक वक्तव्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जिसे रेखांकित किया जाना आवश्यक है। उसकी चर्चा आगे करते हैं, उसके पहले यह बताना आवश्यक है कि अपने पारंपरिक भाषण का आरंभ मोदी ने समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की प्रार्थना के साथ किया। बजट सत्र के पहले प्रधानमंत्री का मां लक्ष्मी को याद करना भारतीय परंपरा का पालन और छद्म पंथ निरपेक्षता का निषेध है। बजट सत्र के पहले मां लक्ष्मी को याद करना प्रधानमंत्री का लाल किला की प्राचीर से लिए गए पंच प्रण के अनुरूप भी है। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में लाल किला की प्राचीर से पंच प्रण लिए थे। उसमें से एक प्रण था गुलामी के सोच से आजादी। बजट सत्र के पहले पूर्व में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने देवी लक्ष्मी का स्मरण किया हो। मोदी ने भारतीयता और धर्म को स्थापित करने के कई छोटे छोटे उपक्रम किए जिसने जनता के मन को छुआ। संसद की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मां लक्ष्मी का स्मरण करना, तीसरी पारी के पहले पूर्ण बजट को विकसित भारत का आधार बजट बताना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर मिशन मोड में आगे बढ़ने की बात की।

अब प्रधानमंत्री के संक्षिप्त भाषण में कही गई उस बात की चर्चा कर लेते हैं जिसका संकेत ऊपर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से मैं देख रहा हूं कि शरारत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और यहां उन शरारतों को हवा देनेवालों की कोई कमी नहीं है। यह पहला सत्र जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी। प्रधानमंत्री जब यह बात कह रहे थे तो उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी थी। बजट सत्र के पहले न तो किसी हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आई, न ही विदेशी मीडिया में भारत को लेकर कोई निगेटिव रिपोर्ट आई। न ही विपक्षी दलों के नेताओं ने विदेश की धरती पर कोई सरकार विरोधी बयान दिया। हिंडनबर्ग, जिसने उद्योगपति अदाणी के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की थी, अपनी दुकान समेटने की घोषणा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उस देश में सक्रिय भारत विरोधी शक्तियों को झटका लगा है। अमेरिका के जो संगठन भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए धन मुहैया करवाते थे, वो भी ट्रंप के गद्दी संभालने के बाद से सशंकित हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने प्रयासों को रोक दिया होगा। वह अलग तरह की रणनीति बनाने में जुटे होंगे, ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। अमेरिका से भारत की संस्थाओं को धन भेजने के नए तरीकों की खोज जारी होगी। गृह मंत्रालय ने भी समाजसेवी संगठनों को विदेश से चंदा लेने पर कानून सम्मत होने की न केवल बात की है, बल्कि उसे कानून सम्मत भी बनाया। इसके अलावा, न तो किसी कोने से मानवाधिकार की बात आई, न ही किसी संस्था ने संसद के बजट सत्र के पहले धार्मिक असहिष्णुता की बात की।

भारत विरोधी ताकतें इनका उपयोग करके देश में अस्थिरता फैलाने का कार्य करती रही हैं। वर्ष 2015 में जब कुछ लेखकों ने सरकार के खिलाफ असहिष्णुता का आरोप लगाकर पुरस्कार वापसी अभियान चलाया था, तब उस तरह के संगठित विरोध को देश ने पहली बार देखा था। एक एक करके खास विचारधारा के लेखक और कलाकार पुरस्कार वापसी करते और पहले इंटरनेट मीडिया पर ये बात तेजी से फैलाई जाती। न्यूज चैनलों पर घंटों चर्चा होती। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म सरकार के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। होता यह है कि ये संस्थाएं अपना अलगोरिद्म बदल देती हैं। सरकार के विरोध वाली पोस्ट अधिक दिखती हैं और समर्थन वाली पोस्ट को बाधित कर देते हैं। पुरस्कार वापसी के समय पूरे देश ने इसको देखा था, नागरिकता संशोधन कानून के समय भी और उसके बाद भी कई अवसरों पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग सरकार के विरोध में माहौल बनाने के लिए किया गया था। छोटी घटना को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि लगने लगता है कि जनमत सरकार के विरोध में है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देश में सत्ता विरोधी माहौल बनाया जाता है। छोटी सी घटना को इतना बड़ा करवा दिया जाता है कि लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा वही है। याद करना चाहिए कि 2015 के बाद के कुछ वर्षों में देश में सबसे बड़ा मुद्दा लिंचिंग को बना दिया गया था। फिर मांसाहारियों के खिलाफ वातावरण बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। छिटपुट घटनाओं के आधार पर ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों या मुसलमानों को जानबूझकर टार्गेट किया जा रहा है।

इन सबके अलावा एक और खेल खेला जाता रहा है, वह है लोकतंत्र को बचाने का। लोकतंत्र के नाम पर इस तरह का खेल खेला जाता रहा है जिससे प्रत्यक्ष रूप से तो यह लगता है कि लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन होता उसके उलट है। लोकतंत्र कमजोर होता है। अरब स्प्रिंग के नाम से हुए आंदोलन को याद करना चाहिए। वर्ष 2010 के आसपास मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों के शासकों को तानाशाह बताकर डिजिटल माध्यम से उनको गिराने की व्यूह रचना कि गई।

दिसंबर, 2010 में ट्यूनीशिया में एक ठेलेवाले के साथ दुर्व्यवहार को आधार बनाकर पूरे देश में सत्ता विरोध की ऐसी हवा बनाई गई कि वहां के राष्ट्रपति को 14 जनवरी 2011 को देश छोड़कर भागना पड़ा। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को राष्ट्रपति बनाया गया। वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों, कथित पंथनिरपेक्ष ताकतों और अरब स्प्रिंग के पहले के राष्ट्रपति के समर्थकों में संघर्ष आरंभ हुआ, जो लंबा चला। केवल ट्यूनीशिया ही क्यों, दुनिया के कई देशों में इस तरह से सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई और उस पर अमल भी हुआ। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स ने अपना अलगोरिद्म बदला था। मोदी विरोधियों को प्रमुखता दी गई थी। इस बदलाव और उसके प्रभाव पर शोध होना चाहिए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी को तानाशाह बताया गया था। यह भ्रम फैलाया गया था कि उनकी पार्टी संविधान बदलने जा रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ। नहीं। विदेश में बैठे कुछ लोग और संस्थाएं भले ही थोड़े समय के लिए चुप हैं, लेकिन यह स्थायी होगा इसमें संदेह है।

भारतीय शेयर बाजार को सरकार से अपेक्षा

शशांक भारद्वाज

शनिवार को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में शेयर मार्केट के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिखा। कुछ दिनों से भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट है। विदेशी निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेच दिए हैं तथा विक्रेता बने हुए हैं। बड़ी संख्या में शेयरों के मूल्यों में 30 से 50 प्रतिशत की कमी देखी गई है। निवेशक मायूस दिख रहा है। ऐसे में शेयर मार्केट को भी कर संबंधी छूट प्रदान करनी चाहिए थी। शेयर मार्केट हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। उसमें गिरावट संपत्ति का क्षय होती है तथा ये लाखों करोड़ रुपये में होती है। भारत में 15 करोड़ डीमैट खाते हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार 45 करोड़ भारतीय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयर मार्केट से जुड़ गए हैं। ऐसे में शेयर मार्केट को सहारा देना भी अब सरकारों का कर्तव्य है। लिहाजा वित्त मंत्री को शेयर मार्केट के भले के लिए भी घोषणाएं करनी चाहिए थीं। यदि लघु अवधि पूंजीगत कर तथा दीर्घ अवधि पूंजीगत कर में कमी कर दी जाती तो शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिलता और मध्यम अवधि में भी मार्केट तेजी आती।

मार्केट में उछाल से कई लाख करोड़ रुपये की संपत्ति वृद्धि होती, विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर मार्केट आकर्षक होता, उनकी बिकवाली रुक जाती और क्रय आता जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा मिलता। साथ ही, मार्केट में तेजी रहती तो सौदे भी बहुत होते हैं, जबकि मंदी में कम हो जाते हैं। अतः वित्त मंत्री ने यदि शेयर के लाभ पर कर कम कर दिया होता तो इसका व्यापक लाभ होता। ऐसा नहीं होने पर बजट के दिन स्वाभाविक उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 26 अंक नीचे ही बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी नकद संभाग में 1327 करोड़ रुपये का विक्रय ही किया। भारतीय निवेशक समुदाय भी वित्त मंत्री पर शेयरों पर कर को लेकर टिप्पणियां करने लगे हैं। ऐसे में इन करों को भी कम करने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

भारतीय शेयर मार्केट में निचले स्तरों से थोड़ा उछाल देखने को मिला है, परंतु यह टिकेगा व बढ़ेगा तभी, जब विदेशी निवेशक विक्रय के स्थान पर क्रय प्रारंभ करेंगे। कुछ प्रमुख वैश्विक संस्थान यूबीएस, जेपी मोर्गन ने भारतीय मार्केट के मूल्यांकन इन स्तरों पर भी महंगे होने की बात कहनी प्रारंभ कर दी है। इस मनोभाव में परिवर्तन के लिए अर्थव्यवस्था ने पुनः तीव्र वृद्धि तथा कंपनियों के लाभ में बढ़त आवश्यक है। तभी ऊंचा मूल्यांकन न्यायोचित होगा। आयकर कम करके सरकार ने खपत बढ़ाने का एक आधार तैयार किया है। ऐसे में यदि शेयर लाभ पर भी कर कम कर दिया जाता तो यह सोने पर सुहागा ही होता। भारतीय शेयर एक मूल्यांकन अड़िट की समयावधि में हैं। महंगे शेयरों में गिरावट के बाद उनमें भी और अधिक गिरावट की ही आशंका है। केवल उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध शेयरों को ही इकट्ठा किया जाना चाहिए। कोई शेयर बहुत गिर गया, इसलिए उसे खरीद लें, इस भाव से बचना चाहिए। पीई अनुपात, मार्केट पूंजीकरण, लाभ का विश्लेषण करके ही निवेश करना उचित माना जाता है।

(लेखक शेयर मामलों के जानकार हैं)

खरी-खरी

सरस्वती पूजनोत्सव

विनोद कुमार विक्की

शिक्षा से कोसों दूर मोहल्ले के लड़कों को बसंत पंचमी की प्रतीक्षा उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार एग्जिट पोल से प्रभावित नेता जी को चुनाव परिणाम घोषित होने का रहता है। बसंत पंचमी के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं का स्वनिर्बाधित क्लब सुरसा की तरह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। माता के ऐसे सीजनल भक्तों ने घर-परिवार में अपने माता-पिता या विद्यालय में शिक्षकों का सम्मान भले ही नहीं किया हो, किंतु बसंत पंचमी को माता सरस्वती के प्रति आस्था प्रदर्शन में कमी नहीं करते। सरस्वती पूजा के नाम पर इन भक्तों की कार्यकुशलता, आर्थिक उपार्जन, प्रसाद वितरण आदि कार्यों में तन्मयता के साथ अद्भुत प्रबंधन भी देखने को मिलता है।

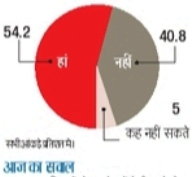

संपूर्ण कैलेंडर वर्ष में निठल्ला घूमने वाले मां के तथाकथित भक्तों की व्यस्तता बसंत पंचमी के पखवाड़ा में उतनी ही बढ़ जाती है जितनी मार्च क्लोजिंग के वक्त बैंक के कर्मचारियों की। माता के आवाहन, स्थापना, डेकोरेशन, प्रसाद, डीजे, विसर्जन आदि से लेकर पूजा के नाम पर चंदा उगाही तक का दायित्व इन्हीं भक्तों के जिम्मेदार कंधों पर टिका होता है। पूजन पूर्व आयोजित बैठक में खर्चों से संबंधित सर्व सम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। मुहल्ले के धन्ना सेठ, दुकानदारों से लेकर बस, ट्रक ड्राइवर आदि से कैसे और कितना चंदा आएगा? मितव्ययिता का ध्यान रखते हुए खर्च में कटौती कर डीजे अथवा रंगारंग कार्यक्रम पर व्यय का प्रबंधन आदि विशेष रूप से दो दिवसीय माता की भक्ति में लीन भक्त जनों का थकान दूर करने के लिए विसर्जन के दौरान अल्कोहल की व्यवस्था पर खास फोकस रहता है। चंदा के नाम पर प्राप्त अतिरिक्त आय से कुछ दिनों तक इन लोगों के खाने-पीने का जुगाड़ हो जाता है।

बहरहाल धार्मिक चंदा के पैसे से खाने-पीने, कमर मटकाने वालों को कोई दोष अथवा पाप नहीं लगता, क्योंकि 'माता शारदे की जय' के उद्घोष मात्र से ही इनका पाप मिट जाता है। रही बात माता की, उनका काम ही है बच्चों के दोष को क्षमा करना। आखिर माता विद्यादायिनी की कृपा से ही इन्हें इस तरह के आयोजन की सद्बुद्धि आती है।

X पोस्ट

लंबे समय के बाद सरकार का उदार चेहरा दिखा है। पहले वेतन आयोग गठित करना और फिर आयकर की छूट सीमा बढ़ाना यही दर्शाता है कि वह नौकरीपेशा वर्ग के बारे में भी सोचती है।
संतोष त्रिवेदी@santoshtrivedi

ट्रंप के संरक्षणवाद और चीन एवं यूरोप की आर्थिक मंदी को देखकर वित्त मंत्री ने भारत के घरेलू उपभोग को बढ़ाकर विकास दर में नई जान फूंकने का रास्ता चुना है। करमुक्त आय को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जो भारत से 20 गुना औसत आय वाले यूरोपीय और अमेरिकी देशों के बराबर है। महंगाई पर काबू रखा गया तो इसका लाभ मिलेगा। शिव कांत@shivkant

अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर नए सिरे से आयात शुल्क लगाया है। इसका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और बाजारों पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। भारत सहित सभी उभरते बाजारों के लिए यह बहुत सतर्क रहने का समय है। वैश्विक निवेशकों के किसी भी संभावित झटके से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी।
उदय कोटक@udaykotak

पौष पूर्णिमा से वसंत तक बस चरैवेति, चरैवेति...

राकेश पांडेय
संपादकीय प्रभारी, प्रयागराज

इस महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान की अंतिम बेला भी शुरू हो गई। कुंभ क्षेत्र में एक बार फिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की जुटान दिख रही है। मौनी अमावस्या पर सुव्यवस्थित से अव्यवस्थित हो चुके महाकुंभ में अब भी वह दर्द महसूस किया जा सकता है जिसमें उस दिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई श्रद्धालु गोलोकवासी हो गए। शासन का उद्देश्य, भावना व प्रयास कितना भी अच्छा हो, सेवा से ओत-प्रोत हो, किंतु उसको भी अक्षम व हठी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मटियामेट कर दिया जाता है, वह इस आयोजन में सीधे तौर पर दिखाई दिया। हालांकि श्रद्धा-आस्था का आवेग इससे ऊपर होता है। मोक्ष की कामना के साथ आने वालों का क्रम इसके बाद भी नहीं टूटा और बसंत पंचमी पर सभी दिशाओं से भक्ति व उल्लास का वही दृश्य दिखाई दिया जो पूर्व के स्नान पर्वों पर देखा जाता रहा है।

प्रयागराज की मान्यताओं के अनुसार यह बड़े हनुमान जी की ही कृपा थी कि बाद में अवैध रूप से बसाई गई टेंट सिटी के 15 काटेज में आग लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिना किसी स्वीकृति के ठेले-खोमचे तक मेला क्षेत्र में न लगाने देने वाले प्रशासन की आंख के सामने 118 काटेज की अवैध टेंट सिटी बस गई और उसे पता ही नहीं चला। जब अधिकारियों का जवाब इस तरह आए कि उन्हें पता नहीं था और वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगें तो गड़बड़ियों की आशंका बढ़ जाती है। अब इस अवैध कृत्य में सब शामिल हैं, यह क्यों न माना जाए? ऐसी सभी टेंट सिटी की जांच कराई जानी चाहिए जो निजी जमीनों पर बसाई गई हैं।

महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर छा रहे संशय के कुहासे को प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त करने के प्रयास पर मान्यता की मुहर तब लग गई, जबकि एक फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुण्य की डुबकी लगा यह विश्वास दिलाया कि अब महाकुंभ की रेल सही पटरी पर दौड़ने लगी है। यहां पहुंचे 73 देशों के राजनयिकों ने विश्वास का यह रंग और गाढ़ा किया। पौष पूर्णिमा और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू हुआ यह मेला बसंत पंचमी आते-आते पूरी तरह से खिल चुका है और सुवासित है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 35 करोड़ श्रद्धालु यहां स्नान करके लौट चुके हैं। विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या किसी भी छोटे से पावन काल में नहीं जुटी थी। संयमित, संकल्पित और सुव्यवस्थित ऐसे स्थान का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इनमें भी तीन अमृत स्नानों पर उमड़ी भीड़ पहले कभी नहीं आई।

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अब तक लगभग 35 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। फाइल

महाकुंभ की हवाओं में बसंत पूरी तरह से घुल गया है। प्रेम के पर्याय बसंत में इस बार लगातार वह दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें अपरिचित लोग को एक-दूसरे को संभाल कर स्नान कराते मिल रहे हैं। आज के अमृत स्नान के बाद अखाड़े एक-दूसरे और अपने भक्तजनों से विदा की अनुमति लेते हुए लौटने की तैयारी में जुट जाएंगे। क्रमशः विदाई की यह प्रक्रिया माघ पूर्णिमा तक चलेगी। विदा लेने की इस बेला में उनकी जीवंतता, आपसी प्रेम, तमाम बाधाओं और जीवन की अनिश्चितता के बावजूद अगले कुंभ पर फिर मिलने के संकल्प और उनकी तैयारियों के प्रति उनकी मंत्रणा जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा भर देती है।

यह सत्य है कि महाकुंभ में अपनों के जाने ने जनमानस को अंदर से झकझोर दिया है। फिर भी इस घटना ने यह सिद्ध किया कि रीति-रिवाजों से बढ़कर वह प्रेम है जो अपनों को, अपनों के लिए अपनों द्वारा होता है। किसी तरह का बंधन न होने के बावजूद अखाड़ों ने मानवीय संवेदनाओं को ऊपर रखते हुए मौनी अमावस्या पर नितांत सादगी से स्नान किया था। बसंत आने के बाद उसकी पंचमी पर होने वाला यह अंतिम अमृत स्नान उसी भव्यता से संपन्न होगा जिसे निहारने के लिए इस ब्रह्मांड के नर-नारी, गंधर्व, किन्नर व देव सभी आकुल रहते हैं। सोमवार का सूर्य अखाड़ों के वैभव और शौर्य का साक्षी होगा और जब अखाड़ों की शोभा यात्रा संगम की ओर बढ़ेगी तो महाकुंभ की दिव्यता और बढ़ जाएगी।

पौष से बसंत तक के तमाम घटनाक्रम सनातन के उस सत्य को दिखलाते हैं कि जहां मानवीय संवेदनाएं सर्वोपरि हैं, वहीं उल्लासमय जीवन भी एक सत्य है। यह हमें बताती हैं कि जीवन शाश्वत चलायमान है। इसे पूर्ण आस्था और उल्लास के साथ जीना चाहिए। क्योंकि स्थिरता जड़ता की ओर ले जाती है, जबकि चलना ही जीवन है। वेद की यह ऋचा भी कभी न थकने के साथ ही चलते रहने का उपदेश देती है कि.... चरैवेति, चरैवेति।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बजट विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक दिख रहा है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या बजट प्रविधानों से उपभोग में तेजी आने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दारू पीकर शाम को घर लौटे पतिदेव,
यदि ये ही उपलब्धि है तो मालिक हैं देव।
तो मालिक हैं देव जरा सोचें महिलाएं,
फिर जाकर वे वोट जिसे चाहे दे आएं।
नेता चुनिए आप मेहनती और जुझारू,
किंतु एक पर एक मुफ्त ना बेचे दारू!
- ओमप्रकाश तिवारी

चुनाव विशेष

दिल्ली विधानसभा का इतिहास

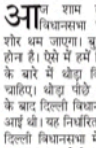

अमित शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, टेक्निया इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, आइपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली

पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली में एक समय ऐसा भी था, जब यहां विधानसभा का अस्तित्व नहीं था। वर्ष 1956 से लेकर 1993 तक यहां विधानसभा नहीं थी

आज शाम तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार को शोर थम जाएगा। बुधवार को मतदान होना है। ऐसे में हमें दिल्ली विधानसभा के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। थोड़ा पीछे चलें तो आजादी के बाद दिल्ली विधानसभा अस्तित्व में आई थी। यह निर्धारित किया गया था कि दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें होंगी। तब व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ सीटों पर दो विधायक निर्वाचित हो सकते थे। इस तरह दिल्ली की कई सीटों पर दो-दो एमएलए चुने गए। दिल्ली विधानसभा का गठन 17 मार्च, 1952 को किया गया था। वर्ष 1952 में ही दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस ने भारी बहुमत से यह चुनाव जीता था। उसने 36 सीटें अपने नाम की थीं। करीब 52 प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले थे। दिल्ली के पहले चुनाव में छह सीटें ऐसी थीं, जिन पर दो एमएलए चुने गए थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1955 में उन्हें हटना पड़ा था। इसके बाद गुरमुख निहाल सिंह ने उनकी जगह ली थी। परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद एक नवंबर 1956 से दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

मेट्रोपालिटन काउंसिल का गठन : केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिए जाने की मांग बनी रही। इसी के तहत दिल्ली के लोगों को एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, 1966 लागू हुआ। इसके तहत दिल्ली में मेट्रोपालिटन काउंसिल का गठन किया गया। इसमें यह तय हुआ कि दिल्ली में मेट्रोपालिटन काउंसिल के 56 निर्वाचित और पांच मनोनीत सदस्य होंगे। दिल्ली के लोग 56 निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन मेट्रोपालिटन काउंसिल के पास कोई विधायी शक्ति नहीं थी। ये केवल सलाहकार के तौर पर काम कर सकती थी। सभी शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के पास दी गईं, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते थे। लेकिन मेट्रोपालिटन काउंसिल के पास कोई विधायी शक्ति न होने के कारण एक पूर्ण विधानसभा की मांग दिल्ली में उठती रही।

सरकारिया समिति ने की राह प्रशस्त : वर्ष 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तब तक दिल्ली की जनसंख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी थी। यह महसूस किया जाना लगा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को अपना पूर्ण प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। राजीव गांधी भी इस मांग से सहमत थे। इसके बाद इस दिशा में पहल करते हुए 24 दिसंबर 1987 को सरकारिया समिति का गठन किया गया। इसे बाद में बालकृष्ण समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 14 दिसंबर, 1989 को सौंपी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली के केंद्र शासित स्वरूप को कायम रखा जाना चाहिए। लेकिन समिति ने दिल्ली में विधानसभा के गठन की भी बात कही जिसे आम लोगों की समस्याओं के निदान के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।

हालांकि बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट आने के पहले ही राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। उसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में बालकृष्ण समिति के प्रस्ताव पर कई वर्षों तक अमल नहीं हो सका। जून 1991 में कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बीच दिल्ली विधानसभा के गठन का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।

दिल्ली विधानसभा : देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया है। फाइल

69वां संविधान संशोधन : नई सरकार बनने के बाद इस प्रस्ताव पर फिर चर्चा शुरू हुई। दिल्ली विधानसभा के गठन की पहल राजीव गांधी ने की थी। ऐसे में नरसिंह राव सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम आगे बढ़ाया। इसके बाद 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली में एक विधानसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। इसने राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद बनाई। इसके जरिए दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में 12 सुरक्षित सीटें हैं। इसके बाद 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा ने इस चुनावों में जीत हासिल की और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से अब तक संबंधित अधिनियम के तहत गठन के अनुरूप ही दिल्ली विधानसभा का संचालन हो रहा है। हर पांच वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग दलों की सरकारें बनी हैं।

सम्पादकीय

अच्छी घोषणाओं की झड़ी, लेकिन क्रियान्वयन पर बड़े सवाल

वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में आम तौर पर कई अच्छी एवं नेक घोषणाएं करते रहे हैं। परंतु, जब इन घोषणाओं की समीक्षा होती है तो कई सवाल मुंह बाए सामने खड़े हो जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अच्छी एवं उत्साह जगाने वाली घोषणाएं की हैं जिनमें आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने, निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने और मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने जैसे कई उपाय शामिल हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि ये घोषणाएं किस हद तक नीतियों में तब्दील होती हैं। सीतारमण ने लगातार आठवां बजट पेश किया है। हरेक वर्ष उनके बजट में कुछ महत्वपूर्ण एवं जरूरी बातें जुड़ती गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बजट को वास्तविकता के धरातल पर उतारना, खासकर राजस्व अनुमानों को लेकर सधा एवं सटीक रवैया अपनाना। इस बजट में भी संशोधित अनुमान की तुलना में अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि सकल कर राजस्व 10.8 प्रतिशत दर से बढ़ने की बात कही गई है। इसका आशय यह है कि टैक्स बॉयंसी 1.06 प्रतिशत रहेगी जिसे हासिल करने में कोई परेशानी पेश नहीं आनी चाहिए। राजस्व व्यय में बढ़ोतरी 6.7 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है इसलिए बजट राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। कर राजस्व के अनुमान वास्तविक रहते हैं तो इससे कर अधिकारियों पर दबाव कम हो जाता है और करदाता भी राहत महसूस करते हैं। हाल के वर्षों में पेश हुए बजट की एक खास बात यह रही है कि उनमें अधिक पारदर्शिता बरती जा रही है और बजट प्रस्तावों से इतर होने वाले खर्च भी शामिल किए जा रहे हैं। बजट में पारदर्शिता बढ़ने से व्यापक आर्थिक हालात पर होने वाले प्रभावों की समीक्षा करने में भी मदद मिलती है। तीसरी अहम बात यह देखने को मिली है कि पिछले बजटों की तरह ही पूंजीगत व्यय में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, चुनावों के कारण लागू पाबंदियों से चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 928 अरब रुपये के बजट प्रस्ताव की तुलना में कम रहे हैं। मगर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में पूंजीगत व्यय के मद में 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में केवल 100 अरब रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कुछ मामलों में यह थोड़ा निराश करने वाला है मगर सरकार को सार्वजनिक निवेश का आकार बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने में किसी एक विकल्प का चयन करना है। चौथी अहम बात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से जुड़ी है जिस पर सरकार का खास ध्यान रहा है। अगले वित्त वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में थोड़ा बेहतर माना जा सकता है। चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय में कमी इसका कारण रहा है। ध्यान देने योग्य बात है कि बजट में राजस्व घाटा 862 अरब रुपये या जीडीपी का 0.4 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो वाकई अच्छी बात होगी। बजट में सबसे महत्वपूर्ण विषय एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण था मगर इसका मामूली जिक्र ही वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह में आगे बढ़ते हुए ऋण एवं जीडीपी अनुपात चालू वित्त वर्ष के 57.1 प्रतिशत से घटाकर 2030-31 तक 50 प्रतिशत (1 प्रतिशत कम या ज्यादा) लाने की बात कही गई है।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

3 फरवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पुर्तगाली तथा उस्मानों के बीच 1503 में दीव की लड़ाई भारत के दीव (अब एक केन्द्र शासित प्रदेश) में हुई।
- सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निज़ाम को 1760 में बुरी तरह हराया।
- विश्व में 1815 में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 फरवरी, 1915 को स्वेज नहर पर जर्मनी और उसमानी शासन की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर हमला किया। आपको बता दें कि स्वेज नहर उस समय ब्रिटेन के नियंत्रण में थी।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में हुयी।
- मुम्बई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा 1925 में शुरू।
- पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला 1934 में शुरू हुआ।
- जावा पर 1942 में पहला जापानी हवाई हमला हुआ।
- जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के बीच स्टालिनग्राड नामक रक्तरंजित युद्ध 3 फरवरी साल 1943 में खत्म हुआ।
- रूस 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ शामिल होने पर सहमत हुआ।
- प्रयाग में 1954 में हुए कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में लगभग 500 से अधिक लोगों की जान गयी।
- बेनेलक्स आर्थिक संघ का गठन 3 फरवरी, 1958 को हुआ।
- 3 फरवरी, साल 1969 के दिन रूस का चालक रहित अंतरिक्ष यान लूना 9 चंद्रमा पर पहली बार पूरी तरह कंट्रोल में रहते हुए उतरा।
- भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की 1970 में तलचर में आधारशिला रखी गई।
- सन 1972 में जापान के सप्पारो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया।
- भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस चक्रको 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल किया गया।
- अंतरिक्षयात्री आईलीन कॉलिन्स 3 फरवरी साल 1995 को अंतरिक्ष शटल को संचालित करने वाली पहली बनीं।
- भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ।
- विश्व आर्थिक मंच की 29 वीं वार्षिक बैठक का 3 फरवरी साल 1999 में स्विजरलैंड के दावोस में समापन हुआ।
- आतंकवाद के खिलाफ, भारत ने उजबेकिस्तान के साथ मिलकर 3 फरवरी, 2003 के दिन ही संयुक्त कार्यदल का गठन किया था।
- भारत के पहले सांसद दलीप सिंह सौंद को सम्मानित करने के लिए 3 फरवरी, साल 2005 के दिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लाए गए विधेयक को आम राय से मंजूरी मिली।
- मिस्र का जहाज् अल सलाम-98 लाल 2006 में सागर में डूबा।
- चीन ने 2007 में मल्टीपरपज नेविगेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया।
- इराक की राजधानी बगदाद में 3 फरवरी साल 2007 में एक बाजार में हुए बम विस्फोट में 135 लोगों की जान चली गई।

विशेष आलेख

प्रयागराज महाकुंभ : परंपरा, पवित्रता और प्रबंधन का अद्वितीय संगम

संजय खाबिया

भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में कुंभ मेला एक अद्वितीय स्थान रखता है। हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धार्मिक मेला है। प्रयागराज महाकुंभ भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का ऐसा पर्व है, जहां करोड़ों लोग मोक्ष और आत्मिक शांति की खोज में जुटते हैं। यह मेला एक ऐसा मंच है, जहां धर्म, समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं का संगम होता है।

कुंभ मेला- पौराणिक कथा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : महाकुंभ का इतिहास पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन की कथा से इसका सीधा संबंध है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अमृत की बूंदें चार स्थानों—हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक—पर गिरीं। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ का उल्लेख रामायण, महाभारत, और पुराणों में मिलता है। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था, जिन्होंने कुंभ को साधु-संतों और जनमानस के आध्यात्मिक संवाद का केंद्र बनाया।

महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व : महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में स्नान की तिथियां विशेष ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। प्रमुख स्नान दिवसों में शामिल हैं

मकर संक्रांति- इस दिन कुंभ का आरंभिक स्नान होता है।

मौनी अमावस्या- इसे सबसे पवित्र दिन माना जाता है।

बसंत पंचमी- इस दिन भी लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं।

अखाड़े और शाही स्नान का महत्व : महाकुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े वे धार्मिक संगठन हैं, जिनमें विभिन्न पंथों के साधु और संत शामिल होते हैं। कुंभ में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें नागा साधु, जो अपनी तपस्या और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, पूरे वैभव के साथ स्नान करते हैं। यह दृश्य श्रद्धा, शक्ति और परंपरा का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है।

प्रमुख अखाड़ों में शामिल हैं-

- जूना अखाड़ा
- निरंजनी अखाड़ा
- महानिर्वाणी अखाड़ा
- अखाड़ा परिषद

प्रयागराज महाकुंभ- भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व : प्रयागराज का संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। गंगा की निर्मलता, यमुना की गंभीरता और सरस्वती की अदृश्यता इस स्थल को अद्वितीय बनाती हैं। संगम पर स्नान भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म और शुद्धिकरण का प्रतीक है। महाकुंभ मेले में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। विभिन्न पंडालों में धार्मिक प्रवचन, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करते हैं।

कुंभ मेले का प्रशासनिक और प्रबंधन पक्ष : प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन एक विशाल प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल का उदाहरण है। करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना किसी चुनौती से कम नहीं है।

प्रमुख प्रबंधन चुनौतियां और समाधान

भीड़ प्रबंधन : लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस का व्यापक इंतजाम किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल और मार्गदर्शन के लिए डिजिटल साइनेज और सूचना केंद्र स्थापित किए जाते हैं।

स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं : कुंभ मेले में स्वच्छता बनाए रखना प्रमुख चुनौती होती है। हजारों शौचालयों और जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस सेवाएं हर समय उपलब्ध रहती हैं।

डिजिटल तकनीक का उपयोग : कुंभ में ड्रोन निगरानी, कैमरा निगरानी और मोबाइल एप्स का उपयोग किया गया। मेला स्थल पर फ्री वाई-फाई और रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया।

आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव : महाकुंभ मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा देता है। लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की उपस्थिति से होटल, परिवहन और खाद्य व्यवसायों को लाभ होता है हस्तशिल्प और लोक कलाओं को भी कुंभ मेले के दौरान बढ़ावा मिलता है। पर्यटन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष पैकेज और टूरिस्ट गाइड सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियां और समाधान : कुंभ मेले के दौरान नदी प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती है। गंगा और यमुना की स्वच्छता सुनिश्चित करना आवश्यक है। नमामि गंगे परियोजना के तहत संगम क्षेत्र में कई सफाई अभियान चलाए गए। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

महाकुंभ-आध्यात्मिकता से परे : महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक सीख है। यहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोग एक साथ आते हैं, जिससे यह सामाजिक समरसता और वैश्विक एकता का प्रतीक बनता है।

वैश्विक मान्यता : यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह आयोजन अब वैश्विक स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है।

विकसित भारत का विजन दिखाता बजट!

सुनिल महता

वसंत पंचमी से एक दिन पूर्व और महाकुंभ के बीच वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट ने नौकरीपेशा लोगों और मध्यम वर्ग को अच्छी राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की यह घोषणा विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर लेकर आई कि 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस राहत का हर कोई बहुत समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि भारत निर्माण में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है, इससे निश्चित ही हमारे देश की प्रगति को नये पंख लगेंगे।

जानकारी देना चाहूंगा कि इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले ज्ञान (जी-गरीब, वाई-युवा, ए-अन्नदाता, एन-नारी) नाम के समूह पर किया गया है। हालांकि बजट में उन सभी क्षेत्रों की बेहतरी पर जोर है, जो 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। यह काबिले-तारीफ है कि जीवनरक्षक दवाओं से टैक्स को हटा दिया गया है। कहना चाहूंगा कि जिला अस्पतालों में कैंसर-डे केयर सेंटर की शुरुआत से कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी। गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती करने का फैसला वाकई बहुत ही सराहनीय है। इससे आने वाले समय में भारत मेडिकल पर्यटन का केंद्र बन सकेगा।केंद्रीय बजट में लगातार दूसरी बार रेलवे को रेकॉर्ड 2.64 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 4.60 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अलग-अलग श्रेणियों की करीब 350 नई ट्रेनें संचालित(200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत ट्रेनें) करने की घोषणा की गई है, इससे विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि प्रस्तुत बजट से विभिन्न क्षेत्रों में जहां एक ओर नये रोजगारों और व्यवसायों का सृजन हो सकेगा वहीं दूसरी ओर निर्माण क्षेत्र में भी अभूतपूर्व तेजी आएगी। बजट में शिक्षा के क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से देश में पांच नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी बात कही गई है। युवाओं व पेशेवरों को एआइ तकनीक का प्रशिक्षण मिलने से भारत एआइ के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। कहना गलत नहीं होगा कि बजट बचत, उपभोग और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाला है, इससे देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। सच तो यह है कि बजट में गरीबों, किसानों और समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। जानकारी देना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसानों को अपनी फसल बोने के लिए बैंक से ज्यादा लोन मिल सकेगा। सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी अपग्रेड और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा।अच्छी बात यह है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, बजट में स्मार्ट फोन और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की लागत पर पड़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमतों में भी काफी गिरावट आएगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियो हमारी आज की शख्सियत कॉलम की स्टार हैं टॉपर आईएएस डॉ.भारती दीक्षित जोकि आज मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पदेन ट्रॉमा आयुक्त, राजस्थान जयपुर पद को सुशोभित कर रही हैं। 4 सितम्बर सन1987 को दिल्ली में जन्मी भारती शुरू से ही होनहार रही हैं। डाक्टरी के पेशे से जिला कलक्टर तक के सफर में क्या अद्भुत अंदाज रहा इनका जोकि युवाओं के लिए सच में किसी आदर्श से कम नही। एमबीबीएस(चिकित्सा) सार्वजनिक निजी भागीदारी पर प्रमाणपत्र बीएससी (चिकित्सा विज्ञान) करने के बाद सिविल सर्विसेज मे आई और सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) जयपुर रही। प्रशिक्षणाधीन एलबीएसएनएए मसूरी (द्वितीय चरण)। सहायक सचिव, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स ऐजेन्सी, जयपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर। संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त, अजमेर अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान जयपुर जैसे बड़े पदों का अतिरिक्त भार भी संभाला। डॉक्टर बनने के बाद भी मन नही माना और आईएएस बनने का सपना दिखाने लगा ऐसे मे भारती दीक्षित ने ठाना जिसे पूरा किया और 2013 मे भारती दीक्षित ने पहले ही प्रयास मे 5 वी रेंक लाकर ये दिखा दिया कि यदि इंसान तबीयत से पत्थर आसमां मे फेंकने की ठान ले तो सच मे आसमां मे छेद किया जा सकता है। इनके पति आशीष मोदी भी आईएएस हैं जोकि इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक पद को सुशोभित कर रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

डॉ.भारती दीक्षित
(आई.ए.एस)

स्पक शर्मा

2025_033

बढ़ता राजस्थान

Suduko

			4	3	2		8	5
3		7	6	1		9	4	
2	8	4	9		5	3		
	3	1			6	5		4
9	6	5				8		1
4			5					
						4		
				6				3
1	4		7	5	9			

Ans_2025_032

6	8	2	1	3	9	5	7	4
7	4	5	8	2	6	3	9	1
9	1	3	7	4	5	2	6	8
4	6	9	2	8	3	7	1	5
5	7	8	6	1	4	9	3	2
2	3	1	5	9	7	8	4	6
8	2	7	9	6	1	4	5	3
3	5	6	4	7	2	1	8	9
1	9	4	3	5	8	6	2	7

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे कामों में और जटिल मुद्दों को सुलझाने तथा सकारात्मक ऊर्जा को संरक्षित करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह सकारात्मकता हमें संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

काम की भागदौड़ के कारण परिजनों के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। हानिकर विचार, वर्तन और आयोजन से दूर रहें। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। कहीं जाने का कार्यक्रम आज हो सकें, तो टाल दें। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

वृष

नौकरी में पदोन्नति होगी। गृहस्थ जीवन में भी आनंद का वातावरण छाया रहेगा। व्यापार के उद्देश्य से कहीं बाहर भी जाना हो सकता है। आज स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम रहने की संभावना है। शारीरिक रूप से आलस्य की भावना रहेगी।

मिथुन

आर्थिक दृष्टिकोण से सावधानी बरतने का समय है। आज नकारात्मक मानसिकता के साथ व्यवहार न करें। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे। मन में दुख और असंतोष की भावना हो सकती है।

कर्क

पारिवारिक वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। परिजनों के साथ गलतफहमी न हो इसका ध्यान रखें। अभ्यास में अभिरुचि होते हुए भी विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होगा। अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। धन का अधिक खर्च होगा।

सिंह

क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपके अहम को कोई चोट न पहुंचे और आपका किसी से झगड़ा न हो, इसका ध्यान रखें। शारीरिक रूप से शिथिलता और मानसिक रूप से चिंता बनी रहेगी।

कन्या

मित्रों और स्वजनों के साथ वैचारिक स्तर पर मनमुटाव हो सकता है। स्वभाव में उग्रता और क्रोध की भावना रहेगी। धार्मिक काम में धन का खर्च होगा। धन का आकस्मिक व्यय हो सकता है। विवाद या झगड़े से हर संभव दूर रहें।

तुला

नई परियोजना की शुरुआत के लिए आज दिन शुभ है। सरकार की ओर से लाभ मिलने संभावना है। छोटे प्रवास का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, करीबियों या पड़ोसियों के साथ पुरानी अनबन की घटना में सकारात्मक परिणाम आएगा।

वृश्चिक

विवाहोत्सुक लोगों को जीवन साथी प्राप्त होने के योग हैं। रुचिकर भोजन प्राप्त होगा। आज का दिन आप के लिए शुभ फलदायी होगा। व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। काम में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी।

धनु

आज आप में आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। पिता और बड़ों से लाभ होगा। सामाजिक रूप से मान-सम्मान में वृद्धि होगी। वाणी और व्यवहार उग्रता न हो, इसका ध्यान रखें।

मकर

आज आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे। इस काम का फल भी आपको अपेक्षानुसार मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा तथा आर्थिक व्यवहार करने में सफलता प्राप्त होगी।

कुंभ

आपके लिए आज का दिन शुभफलदायी होगा। विविध क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। मित्रों के पीछे खर्च भी होगा और उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। किसी प्रवास या पर्यटन स्थल पर जाने से दिन रोमांचक बन जाएगा।

मीन

आज आपको अपने उग्र स्वभाव पर संयम रखने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव होगा। अधिक परिश्रम के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है। मानसिक रूप से भी चिंता बनी रहेगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीएपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक

चिंतन

बजट में घरेलू उपभोग व मांग बढ़ाने पर जोर

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू उपभोग व मांग बढ़ाने पर जोर दिया है। चालू वित्त वर्ष में सुस्त ग्रोथ का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के लिए अगले वित्त वर्ष में भी जीडीपी दर सात फीसदी के नीचे रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। आर्थिक वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। बजट वर्ष के लिए 6.3 से 6.8 फीसदी के बीच जीडीपी के रहने का अनुमान है। अभी कुछ वर्षों से देश में आर्थिक सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने खपत बढ़ाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया है और सार्वजनिक खर्च में भी कमी आई है। हालांकि सरकार पर सब्सिडी बोझ में बहुत कमी नहीं आई है। ऐसे में पूरी उम्मीद यही थी कि सरकार इस बजट में सरकारी खर्च व खपत बढ़ाने के उपाय करेगी और आर्थिक सुधार के अगले चरण की शुरुआत करेगी। एक फरवरी को संसद में पेश बजट में 12.75 लाख रुपये तक सालाना आय को कर मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है, नई टैक्स रिजीम में स्लैब में बदलाव किया है, नया आयकर कानून लाने का वादा किया गया है। आयकर को लेकर सरकार का यह बोल्ड स्टेप है। नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में अत्यधिक सुधार की जरूरत थी, पर बजट में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। शायद आगे जीएसटी के सरलीकरण पर विचार हो। फूड व फर्टिलाइजर सब्सिडी मामूली बढ़त के साथ जारी रखी गई है। बीमा में शर्त के साथ सौ फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई है, लेकिन दूसरे कई क्षेत्र हैं, जिसमें एफडीआई सीमा बढ़ाने की जरूरत थी। न्यूटेक व न्यूएज इकोनॉमी में रेगुलेशन के साथ और अधिक उदारीकृत निवेश नियम की आवश्यकता है। बजट में इस पर स्पष्टता नहीं है। हेल्थ सेक्टर में इरडा, ट्राई व सेबी की तरह व्यापक नियामक की जरूरत है, बजट में इस पर कुछ नहीं है, लेकिन इसमें नियामक की जरूरत के अवलोकन के लिए एक समिति गठन का प्रस्ताव है। शायद समिति इस बिंदु पर विचार करे। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जारी खर्च को जारी रखा गया है। इस बजट में भी 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले तीन बजट से आवंटन 10 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है। इस बजट में भी रेल, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को तवज्जो दी गई है। हालांकि सरकार ने पूंजी व्यय बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन कर्ज अदायगी पर बड़े ब्याज भार को कम करने के लिए विनिवेश को लेकर कोई नया ऐलान नहीं किया गया है। सरकार विनिवेश की गति बढ़ा कर अगर कर्ज कम करेगी तो ब्याज भार को कम किया जा सकेगा। सरकार को बड़ी रकम ब्याज चुकाने पर खर्च करना पड़ रहा है। बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया गया है। सरकार ने टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचा जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत का वादा किया है। परमाणु ऊर्जा मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कुछ घोषणाएं सराहनीय है, राजनीति के साथ हेडलाइन पर ध्यान दिया गया है, लेकिन उद्योग क्षेत्र व रोजगार सृजन के लिहाज से सरकार के पास बजट को और प्रोग्रेसिव और आर्थिक सुधार को गति देने वाला बनाया जा सकता था। अभी सरकार के पास इसके लिए पूरा मौका भी था।

विश्लेषण
अरविंद जयतिलक

उम्मीदों की कसौटी पर खरा बजट

देश के विपक्षी दल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट की चाहे जितनी निंदा और आलोचना करें लेकिन देश का आमजन, मध्यम वर्ग, कारपोरेट जगत और शेयर बाजार बजट से उत्साहित और संतुष्ट है। इसलिए कि वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को गतिशील करने के लिए करों का बोझ बढ़ाने और सब्सिडी पर कैंची चलाने से परहेज करते हुए बजट को मानवीय रूप देने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने सभी वर्गों का भरपूर ख्याल रखते हुए विकास का क्रांतिकारी बजट पेश किया है। उन्होंने बजट में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी है। माना जा रहा है कि इस बजट से औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के पहिये नाच उठेंगे और वर्षों से आस लगाए मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में पैसा आएगा। गौर करें तो यह बजट मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, भरपूर निवेश, टिकाऊ विकास और अधिकतम रोजगार की संभावनाओं से लैस है। वित्तमंत्री ने टैक्स दर में व्यापक बदलाव किया है जिससे कि बाजार में नकदी की आमद बढ़ेगी। बजट के आंकड़ों पर नजर डालें तो उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषिय घाटा जीडीपी का 4.4 फीसदी और सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान है जो कि जीडीपी का 3.1 फीसदी है। देखें तो खर्च बढ़ने के बावजूद सरकार घाटा को नियंत्रित करने में सफल रही है। चूंकि बजट के प्रावधानों के मुताबिक पूंजीगत खर्च में रिकार्ड इजाफा हुआ है उससे सार्वजनिक ढांचे को मजबूती मिलनी तय है और इससे रोजगार भी सृजित होंगे। इस वित्त वर्ष में विकास दर 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है जो कि वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से संतोषजनक है। सरकारी खर्च बढ़ाने के कारण यह बजट युवाओं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों और अनुसूचित जनजातियों के हित में होगा। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से अगले एक वर्ष में तकरीबन कई लाख नौकरियां सृजित होंगी और बेरोजगारी का ग्राफ गिरेगा। वित्तमंत्री ने सैलरीड क्लास के लिए 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स न लगाकर मध्यम वर्ग को भारी राहत दी है। मजेदार बात यह कि सैलरीड क्लास के लोगों को 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडेक्शन का फायदा भी मिलता रहेगा। वित्तमंत्री ने बजट में विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि को मजबूती देने के लिए राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार में मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। सरकार अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। निःसंदेह इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी और उनका जीवन सुधरेगा। वित्तमंत्री ने कपास उत्पादन से जुड़े किसानों की बेहतरी के लिए 5 वर्षीय मिशन का ऐलान किया है जिससे किसानों का कल्याण होगा। कृषि कार्य से जुड़े देश के करोड़ों किसानों को कृषि उपक्रम हेतु नकदी की कमी न हो, इसके लिए वित्तमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। यह किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फुटवियर, लेदर और खिलौने उत्पादन से जुड़े लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वित्तमंत्री की पहल सराहनीय है। उन्होंने नवाचार में निवेश को बढ़ावा देने, डीपटेक फंड ऑफ फंडस, प्रौद्योगिकी अनुसंधान फैलोशिप, नेशनल जिओ स्पेटियल मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर और पर्यटन पर विशेष फोकस की है। इसके अलावा उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये आवंटित की है। यह पिछले बजट से 13567 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले बजट से तकरीबन 9 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बजट में व्यापक इजाफा किया है। कुल मिलाकर वित्तमंत्री का बजट अर्थव्यवस्था को गतिशील और भारत राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सियासत
राज कुमार सिंह

दिल्ली चुनाव में कांटे की टक्कर

दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरह मुफ्त रेवड़ियों के वादों पर लड़ा जा रहा है। दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप इस बार भी मुफ्त रेवड़ियों के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है तो रेवड़ी-राजनीति को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा भी रेवड़ियां बांटने की स्पर्धा में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। कभी लगातार 15 साल दिल्ली में सत्तारूढ़ रही, पर पिछले दो विधानसभा चुनावों में खाता तक खोलने में नाकाम कांग्रेस की भी सारी उम्मीदें मुफ्त रेवड़ियों के वादों पर ही टिकी हैं। चुनाव घोषणापत्रों के इस दौर में, भाजपा दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक तीन हिस्सों में अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर चुकी है।

दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहा है। मतदाताओं का मन तो आठ फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन यह तय है कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर है। कहने को तो कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी खोई जमीन हथियाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है लेकिन धरातल पर भाजपा और आप में ही सीधी टक्कर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरह मुफ्त रेवड़ियों के वादों पर लड़ा जा रहा है। दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप इस बार भी मुफ्त रेवड़ियों के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है तो रेवड़ी-राजनीति को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा भी रेवड़ियां बांटने की स्पर्धा में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। कभी लगातार 15 साल दिल्ली में सत्तारूढ़ रही, पर पिछले दो विधानसभा चुनावों में खाता तक खोलने में नाकाम कांग्रेस की भी सारी उम्मीदें मुफ्त रेवड़ियों के वादों पर ही टिकी हैं। चुनाव घोषणापत्रों के नये नामकरण के इस दौर में, भाजपा दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक तीन हिस्सों में अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर चुकी है। प्रतिद्वंद्वियों के मुद्दों को मात देने कवायद में ही ऐसा करना पड़ रहा है। पानी, बिजली और महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त तथा बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य से अपनी अलग पहचान बनानेवाली आप ने अभी तक लागू न हो पायी महिला सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का ऐलान किया तो कांग्रेस और भाजपा ने 2500 रुपये का वादा कर दिया।

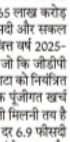

यह प्रतिस्पर्धा हर वर्ग को लुभाने के लिए की गयी घोषणाओं में दिखती है। आप ने पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन का ऐलान किया तो कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा वोट बैंक बन चुके पूर्वांचलियों के लिए विकास बोर्ड बनाने का ही वादा कर दिया है। कांग्रेस युवाओं को एक साल की इंटर्नशिप और साढ़े आठ हजार रुपये देने मासिक देने का वायदा कर रही है तो भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठनेवाले छात्रों को 15 हजार रुपये देने की बात कही है। कांग्रेस की तरह भाजपा भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो देगी ही, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी दिया जायेगा। मुफ्त रेवड़ियों की यह फेहरिस्त लंबी है, पर विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था में भी ऐसी विडंबना पर शर्म किसी के चेहरे पर नजर नहीं आती। पांच साल तक सत्ता में रही भाजपा और फिर 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में होने के तर्क के सहारे अपनी वादों की राजनीति का बचाव करते हैं तो दस साल से सत्तारूढ़ आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी यमुना सफाई जैसे अधूरे वादों के बचाव में पहले ढाई साल 'कोरोना' और फिर 'जेल का खेल' का तर्क देते हुए 15 गारंटियां बांट दी हैं। मुफ्त रेवड़ियों का यह चुनावी खेल तब परवान चढ़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग भी मुफ्त रेवड़ियों की राजनीति के आर्थिक खतरों पर चिंता जता चुके हैं। खुद सवालों से घिरे चुनाव आयोग की बात न भी करें तो देश की सर्वोच्च अदालत तक इस प्रवृत्ति पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन इस सबसे बेपरवाह सत्ता के खिलाड़ी इन्हें जन कल्याण योजनाएं बता रहे हैं। रेवड़ी-

राजनीति के चुनावी असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिन-रात केजरीवाल को कोसनेवाली भाजपा को कहना पड़ रहा है कि अगर वह सत्ता में आयी तो भी आप सरकार की जन कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। हां, लोकतंत्र में जिस जनता को जनार्दन बताया जाता है, उसे यह बताने की जहमत कोई दल नहीं उठा रहा कि जन कल्याण के नाम पर बांटी जा रही रेवड़ियों पर कितना खर्च आयेगा और वह कहां से जुटाया जायेगा? सत्ता के तीनों दावेदार अन्य राज्यों में एक-दूसरे के चुनावी वादों और उनके पूरे होने पर सवाल उठाते हुए अपने 'ट्रैक रिकॉर्ड' के लिए खुद ही अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 500 में से 499 चुनावी वादे पूरे करने के साथ ही उनकी पार्टी का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। कांग्रेस और आप, लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भाजपा के अधूरे चुनावी वायदे गिना रहे हैं। भाजपा भी पंजाब में आप तथा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी वादों को अधूरा बता रही है। इन आरोप-प्रत्यारोपों का सच जो भी हो, इतना तय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली में इस बार भी चुनाव मुफ्त रेवड़ियों के वादों पर ही लड़ा जा रहा है। महंगाई पर अंकुश और रोजगार बढ़ाने का विजन किसी राजनीतिक दल ने पेश नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त रेवड़ियों के वादों के आधार पर ही अपनी पसंद का राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनना होगा। हां, इसमें उनका राजनीतिक रुझान और संबंधित दल की वादे पूरे करने में विश्वसनीयता एक कारक बन सकता है, पर उन्हें याद रखना होगा कि मुफ्त रेवड़ियों की इसी राजनीति के चलते अभी तक 'सरप्लस' रहने वाले दिल्ली के बजट पर घाटे की तलवार लटक रही है। हाल ही में आयी भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि खासकर आधी आबादी के वोट बटोरने के लिए घोषित की जा रही मुफ्त योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बन रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खाते में सीधे नकद भेजने वाली योजनाओं का बढ़ता चुनावी चलन एक खतरनाक आर्थिक संकेत है। दिल्ली में 1000 रुपये मासिक महिला सम्मान योजना पर ही बजट का तीन प्रतिशत खर्च होने का अनुमान था। अगर उसे बढ़ा कर 2100 या 2500 रुपये किया गया तो वह और बढ़ जायेगा। पश्चिम बंगाल में लागू लक्ष्मी भंडार योजना पर होने वाला 14400 करोड़ रुपये का खर्च राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का छह प्रतिशत है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के लिए आवंटित 28608 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्ति का 11 प्रतिशत बनता है। देश के आठ राज्यों में ही महिलाओं को मुफ्त नकदी बांटने वाली योजनाओं का खर्च डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। आधी आबादी को बिना काम नकदी, चुनाव कर जीत सत्ता पाने का कारगर फॉर्मूला बन रहा है। आने वाले समय में यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी ही। ऐसे में दीर्घकालीन सर्वांगीण विकास की सोच और योजनाएं हमारे नीति-नियंताओं के एजेंडा से गायब ही होती जायेंगी। सतही तर्क हो सकता है कि जब मतदाता ही आत्मकेंद्रित सोच से ग्रस्त हैं तो उनके वोट पाने के लिए की जाने वाली राजनीति की सोच व्यापक और विकासपरक कैसे हो सकती है? देश की राजधानी दिल्ली की यह चुनावी तस्वीर मुफ्त रेवड़ियों की चुनावी राजनीति से मुक्ति की उम्मीद तो हरगिज नहीं जगाती। इसलिए राज्यों पर बढ़ते कर्ज का बोझ कम होने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। याद यह भी रखना चाहिए राज्य पर कर्ज का बोझ अंततः नागरिकों पर ही कर्ज का बोझ है, क्योंकि राजनेता तो सत्ता-सुख भोग कर आते-जाते रहेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

राम सब घट मेरा साइयां

संकलित
दर्शन

पूरे संसार में राम का निवास है, सबमें भगवान हैं और हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। कबीर ने कहा है-'राम सब घट मेरा साइयां'... राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। सदा सर्वदा सबके हृदय में रहेंगे, लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताओं के कारण कभी-कभी हम राम को साधन बना बैठते हैं। इसलिए हम राम को सही रूप में नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमें सिया राम के दर्शन होने लगें तो तमाम भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जातीय आधार पर भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए धर्माचार्यों को आगे आना होगा। धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र, अंतिम व्यक्ति पूज्य होना चाहिए। अगर अंतिम व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक पहुंचें। भारतीय दर्शन में इहलोक और परलोक की बात आती है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। दूसरों के कल्याण की भावना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम व्यापक व विराट की संतान हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण का भारतीय सोच पूरे विश्व के कल्याण का सोच है।

तुलसीदास जी द्वारा श्रीराम के दर्शन का उपाय

संकलित
प्रेरणा

एक ब्राह्मण दिनभर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम-राम रटता। संध्या के समय श्रीहनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहाः उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए। ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहाः आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान् के दर्शन करवा सकते है। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहाः ठीक है यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाढ़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पडो। भगवान् के दर्शन हो जायेंगे। वह त्रिशूल गाडकर वृक्षपर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई।

एक घुडसवार उधर से जा रहा था, उसने पूछाः पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोलाः तुलसीदास जी ने कहा है पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तुम्हे भगवान् श्रीराम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहाः क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोलाः जी हाँ ! वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिनमें प्रेम-भाव हो एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है।

अंतर्मन

आज की पाती

कब बुझेगी नक्सलवाद की आग?

देश में आतंकवाद से भी खतरनाक समस्या नक्सलवाद की है जो कि देश के कुछ राज्यों में आफत बनी हुई है। नक्सलवाद के होने के क्या कारण है, इस पर कहा जा सकता है कि शासन और प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार भी इसका कारण हो सकता है। जब किसी को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी और जब भ्रष्टाचार के सताए लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ता भी अपना सकते है। हमारे देश में नक्सलवाद के नाम पर कम्युनिस्टों ने आतंकवाद से भी बड़ी समस्या पैदा कर दी है। साम्यवादी विचारधारा हिंसक विचारधारा से भरी होती है। हमारे देश में नक्सलवादी सरकार और सरकारीतंत्र में फैले भ्रष्टाचार के सताए गरीब लोगों को बहला-फुसलाकर हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

- संजय गुप्ता, जगदलपुर

ट्रेंड

शुभकामनाएं

हमने मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाने को सम्मान दिया है, लेकिन कांग्रेस और 'आप'दा वाले इसकी खेती से जुड़े मेरे दलित परिवारों का भी मजाक उड़ा रहे है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत का गौरव

डबल इंजन की सरकार से भारत का गौरव बढ़ रहा है, सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है। श्री अयोध्या धाम के विकास के लिए, श्री अयोध्या धाम के सम्मान के लिए भाजपा आवश्यक है।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

अमित शाह बौखलाए

बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। अमित शाह बुरी तरह से बौखला गए है। अब वो दिल्ली मजबूरीवश पुलिस खड़े होकर जनता पर खुले आम हो रही हिंसा को देखती रहती है। हिंसा के बाद गुंडो को भगा दिया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर फर्जी केस कर दिया जाता है।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

परिजनों को नहीं मिल रहे शव

ये समाचार दुखद है कि महाकुंभ हादसे में मारे गये श्रद्धालुओं के शव लेने के लिए, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन में खड़े है पर उनको शव नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे कोई सहायता-सांत्वना राशि भी नहीं मांग रहे। सरकार ध्यान दे।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

करंट अफेयर

माशतिले ने सराही हिंदू समुदाय की भूमिका

दक्षिण आफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले ने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण (बीएपीएस) संस्था के बहु-सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर के प्रथम चरण का उद्घाटन करते हुए कहा कि बीएपीएस के सिद्धांत दक्षिण आफ्रीका के राष्ट्रीय लोकाचार उबुंटू से मिलते-जुलते हैं। माशातिले ने स्थानीय हिंदू समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा, "हमें राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका पर विचार करना चाहिए। इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्य समृद्ध हैं और इसने हमारे विविधतापूर्ण समाज के सामाजिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" आधिकारिक उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने बीएपीएस और दक्षिण आफ्रीकी लोकाचार के बीच समानताएं रेखांकित करने का प्रयास किया। माशातिले ने बीएपीएस की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा, "धर्म, सेवा और एकता के बीएपीएस के सिद्धांत वास्तव में साझा मानवता और अंतरसंबंध में विश्वास से जुड़े हमारे राष्ट्रीय लोकाचार उबुंटू से काफी मुलते-जुलते हैं।"

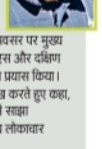

ऑफ बीट

जोड़ों के दर्द से लगाया जा सकता है मौसम का अंदाज

सदियों से लोग दावा करते रहे हैं कि उनके जोड़ों के दर्द से मौसम में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है, अकसर बारिश या सर्दी के मौसम से पहले वे तकलीफ बढ़ने की बात कहते हैं। दर्द के पैमाने और अवधि को देखते हुए ये दावे सही भी लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अब भी इसको लेकर विरोधाभास हैं। वायुमंडलीय दाब में बदलाव से लेकर तापमान में उतार-चढ़ाव तक, कई सिद्धांतों से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि पर्यावरणीय कारक जोड़ों के दर्द को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। गतिशील जोड़ों की संरचना जटिल होती है, जो श्लेष द्रव (सिनोवियल फ्लूड) के कारण गद्देदार होती हैं। 'सिनोवियल फ्लूड' एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जो जोड़ों को चिकना बनाता है। स्वस्थ जोड़ों में ये घटक सुचारू रूप से अपना काम करते हैं और जोड़ों में दर्द नहीं होता। हालांकि, जब जोड़ों की उपास्थि को 'ऑस्टियोआर्थराइटिस' जैसी समस्या के दौरान क्षति होती है या संधिवात गठिया की वजह से सूजन होती है, तो पर्यावरण में सूक्ष्म परिवर्तन भी तीव्रता से महसूस किए जा सकते हैं। एक प्रमुख परिकल्पना यह बताती है कि वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन सीधे तौर पर जोड़ों की तकलीफ को प्रभावित कर सकता है।

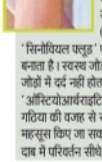

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 3 फरवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सजगता अमरता का पथ है, असजगता मरण का पथ है। जो सजग रहते हैं, वे कभी नहीं मरते और जो सजग नहीं हैं, वे पहले ही मर चुके हैं।
-बुद्ध

राहतकारी बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए बजट में मध्यम वर्ग के लिए राहत की बड़ी सौगात दी है। यह कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कर नहीं लगेगा जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बच सकेगा। फलस्वरूप घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में रवानी आने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वित्त मंत्री ने शनिवार को लोक सभा में वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जो उनका लगातार आठवां बजट रहा, जो कीर्तिमान है। इस राहत से करीब एक करोड़ लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा है कि 'यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा'। बेशक, बजट में जिस प्रकार से आयकर से राहत दी गई है, वह बाकी सभी बजट प्रावधानों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण दिखलाई पड़ रही है। हालांकि हर बजटीय प्रावधान खासे विमर्श के बाद किया जाता है। लेकिन आयकर में राहत महत्त्वपूर्ण है क्यों कि अरसे से इस बाबत मांग की जा रही थी। अब यह राहत मिली है, तो इसे कुछ लोग चुनाव के मद्देनजर किया गया बदलाव करार दे रहे हैं। इस साल के आखिर में बिहार और इसी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार के लिए भी पैकेज घोषित किया है, और आयकर में राहत से एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली के 85 प्रतिशत करदाताओं को अब आयकर नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल, आम बजट से चुनावी से इतर अनेक लाभ मिलने तय हैं। महंगाई कम करने के साथ ही बजट रोजगार सृजन में सहायक होगा। रक्षा क्षेत्र और पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के साथ ही नियामक सुधारों पर बल दिया गया है। वरिष्ठ जन की एक लाख रुपये तक की ब्याज आय को कर-मुक्त रखा गया है, जो यकीनन सराहनीय है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी उत्साहजनक ऐलान है। स्वास्थ्य क्षेत्र और ईवीएम से जुड़ खर्चों के लिए भी खासा आवंटन है। वित्त मंत्री ने रेल बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति ही 2.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बेशक, बजट की आलोचना करने के लिए तमाम तर्क गढ़े जा सकते हैं, लेकिन इतना तो कहना होगा कि बजट समाज के व्यापक वर्ग के हित में दिख रहा है।

गोपन की गरिमा

किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने की महिला की सहमति उसके निजी पलों को वीडियो में कैद करने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपी के कृत्य को अदालत ने स्पष्ट तौर पर ब्लैकमेलिंग बताया। शिकायतकर्ता ने परिचित पुरुष से कर्ज लिया जिसे नौकरी प्राप्त होने के बाद चुकाने का वादा था। इस दरम्यान दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं और वे वाह्ट्सएप पर बातें करने लगे। वीडियो कॉल के दौरान वह जो कहता, महिला वही करती। प्रेमालाप के दौरान दोषी ने उसे बरगला कर कपड़े उतवाए और नग्न वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनबन होने पर दोषी ने यह वीडियो उसके पैतृक गांव के कुछ लोगों व सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि कर्ज की राशि प्राप्त न होने के कारण उसने यह कदम उठाया। चूंकि मामले में महिला मासूम नहीं है। वह विवाहित और परिपक्व है। भावावेशवश, लाभ के लोभ में, मजबूरन या ब्लैकमेलिंग के चलते जो कुछ करने को वह राजी हुई, उस पर अपने धन की वसूली के नाम पर दोषी ने जो तरीका इख्तियार किया वह किसी स्त्री की गरिमा, निजता और अधिकारों पर अतिक्रमण है। हालांकि महिलाओं को सहमति से संबंध बनाने के बावजूद इतना सतर्क और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने से नहीं चूकना चाहिए जो विपरीत स्थितियों में उनके खिलाफ हथियार के तौर पर प्रयोग किया जा सके। पूर्व प्रेमियों के ऐसे दुर्व्यवहार की शिकार लड़कियां अमूमन ब्लैकमेलिंग की शिकायतें करने से भी घबराती हैं। पुरुषों द्वारा अंतरंग संबंधों या नग्न तस्वीरों को हथियार की तरह प्रयोग के प्रति महिलाओं को जागरूक रहना होगा। अपनी सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं को झूठी शान व इज्जत के नाम पर तरह-तरह से शोषित किया जाता है। अमूमन पीड़िताएं इस विषम स्थिति से घबरा कर अपना जीवन ही समाप्त कर लेती हैं। अदालत की सख्त टिप्पणी और कड़ी सजा के जरिए दोषियों को भी सीख दी जानी जरूरी है ताकि वे सहमति से बने संबंधों की गोपनीयता को हथियार बना कर अपने ही हाथ जलाने का जोखिम लेने से घबराएं।

चर्चा/मीना धानिया

'बेचारी' वाले बयान से दिखी बेचारगी

पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति होता है। संसद के बजट सत्र से पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरह से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की उस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा इस दौरान संसद के बजट के सत्र में समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रपतियों द्वारा अभिभाषण दिया गया, लेकिन कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही विपक्ष ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे विवाद खड़ा हो।

राष्ट्रपति का अभिभाषण विपक्ष को पसंद आए जरूरी नहीं, और विपक्ष को इसकी आलोचना का अधिकार होता है। लेकिन यह बात अच्छी नहीं कि देश की अनुभवी नेता राष्ट्रपति पर सतही टिप्पणी करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह कहने की आवश्यकता कतई नहीं थी कि आखिर तक आते-आते राष्ट्रपति बहुत थक गई हैं। हां, राष्ट्रपति के रुक-रुक कर बोलने का मतलब यह नहीं कि वो थक गई हैं। जबकि सोनिया मुर्मू के मुकाबले ज्यादा उम्रदराज हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी को भी इस बयान से नुकसान का बहुत जल्द अहसास हो गया। आनन-फानन में इस नुकसान को पाटने के लिए पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा नमूदार हुईं। उन्हें यह कहना पड़ा कि उनकी मां राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती हैं और उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। हालांकि तब तक सोनिया की वाणी का असर देश भर में पसर चुका था और इस मामले में पार्टी की खासी किरकिरी हो चुकी थी। निश्चित तौर पर सोनिया से ऐसे बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे भी सार्वजनिक जीवन हो या सियासत; जिह्वा की हमेशा से अहम भूमिका रही है।

सोनिया गांधी वैसे कभी हल्का बयान नहीं देती हैं। वो गरिमापूर्ण नेता हैं और इसका हमेशा ख्याल रखती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जिस सामाजिक परिवेश और पृष्ठभूमि से आती हैं, उसे देखते हुए सभी नेताओं को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। साथ ही महामहिम जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को समझना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी सियासी दलों के नेता इस बात की मर्यादा को समझेंगे और किसी के भी खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे न केवल उनका बल्कि सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचे।

मुस्कुराहट देने वाला बजट

मध्यम वर्ग

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्त वर्ष 2025-26 का बजट करदाताओं, निवेशकों तथा मध्यम वर्ग को मुस्कुराहट देते दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री बजट के माध्यम से टैक्स में कटौती और वित्तीय प्रोत्साहनों से मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ा कर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। वित्त मंत्री ने नये टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री किया है। खास बात यह भी है कि बजट के तहत बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की वर्तमान 74 फीसद की सीमा बढ़ा कर 100 फीसद किया गया है। इससे कंपनियों को ज्यादा पैसा मिलेगा और ऐसे में वे अपना विस्तार करेंगी और प्रीमियम भी कम होने से करदाता और मध्यम वर्ग लाभान्वित होगा।

निस्संदेह कोरोना काल के बाद मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए ढेर सारी राहतों का ऐलान किया, वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले विभिन्न बजटों में मध्यम वर्ग की चिंताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ग पर लगाए गए कर की तुलना में इस वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं के जरिए बहुत कम रिटर्न मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बजट सत्र की शुरुआत पर मध्यम वर्ग को सौगात देने के संकेत दिए थे।

साथ ही, वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा पेश की उसमें भी वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले मध्यम वर्ग की वास्तविक आय में कमी आने की बात स्वीकार की थी। ऐसे में वित्त मंत्री कोरोना काल के बाद देश के विकास का इंजन कहे जाने वाले मध्यम वर्ग के निजी उपभोग पर होने वाले खर्च में गिरावट से घटी हुई विकास दर को बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ी हैं। निश्चित रूप से इस बजट से सरकार लंबे समय से लंबित मध्यम वर्ग की आर्थिक वित्तीय शिकायतों का समाधान करते हुए आर्थिक वृद्धि की गति को फिर से तेज कर उपयुक्त कर राहत से एक अच्छा आर्थिक चक्र करने की डगर पर आगे बढ़ी है।

निश्चित रूप से मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करने से खपत बढ़ेगी। इससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी और कर योग्य आय वालों का आधार बढ़ेगा। मजबूत मध्यम वर्ग भारत के ऊंचे विकास के सपने को आकार देने का आधार बनते हुए भी दिखाई देगा। गौरतलब है कि बजट 2025-26 के मद्देनजर वित्त मंत्री सीतारमण के पास मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगातार आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांग लगा कर वृद्धि हुई है। ऐसे में करदाताओं, छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बना कर खर्चों और सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश बजट में दिखाई दी है। वित्त मंत्री ने मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नये टैक्स रिजीम की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं को अभूतपूर्व राहतों से लाभांवित किया गया है। नये टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव है ताकि अधिक से अधिक करदाता इसे अपनाने के लिए प्रेरित हों।

बजट 2025-26 के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद रहा। पिछले 10 वर्षों में लगातार आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांग लगा कर वृद्धि हुई है। ऐसे में करदाताओं, छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बना कर खर्चों और सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश बजट में दिखी है

नये बजट के तहत न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव और अतिरिक्त रिबेट की घोषणा की जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आय के विभिन्न स्तरों पर टैक्सपेयर्स को बड़ी बचत का भी मौका मिलेगा। बजट 2025-26 में सीनियर सिटीजन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। नई टैक्स रिजीम के तहत वेतनभोगी वर्ग को 75,000 रुपये की छूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का लाभ बना हुआ है। यद्यपि देश में कर सुधारों से आयकर के संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है, लेकिन अभी आयकर के कर दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां 2025-26 के बजट से वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को आयकर राहत संबंधी उपहार सौंपा है, वहीं उन्होंने बजट में आयकर सुधारों के लिए नई व्यवस्था का ऐलान भी किया है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से भी बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं, या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से 8.09 करोड़ लोगों ने ही आयकर रिटर्न दाखिल किए। इनमें से भी 4.90 करोड़ लोगों ने शून्य कर योग्य आय की सूचना दी। सिर्फ 3.19 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आयकर का योगदान कम बना हुआ है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री ने आयकर सुधारों के तहत आगामी सप्ताह में नया टैक्स बिल लाने की घोषणा की है। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को नई जरूरतों के अनुरूप आसान और प्रभावी बनाना है। नया आयकर कानून मौजूदा कानून में संशोधन भर नहीं होगा, बल्कि पूर्णतया नया कानून होगा। इसके तहत अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। कर विवादों को कम किया जाएगा। टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाया जाएगा।

निश्चित रूप से 2025-26 के बजट में आयकरदाताओं, निवेशकों और मध्यम वर्ग के लिए दी गई टैक्स राहत और किए गए अन्य विशेष प्रावधानों से मध्यम वर्ग की मुस्कुराहट बढ़ेगी। ऐसे में मध्यम वर्ग की बढ़ी क्रय शक्ति खपत में वृद्धि विकास दर और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकती दिखाई देगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम चीनी उद्योग

- चीनी उद्योग में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा कर तीन प्रतिशत करने की क्षमता है। फिलहाल, जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 1.0 से 1.15 प्रतिशत है
- चीनी के निर्यात को नियंत्रित करने की सरकार की नीति फायदेमंद और नुकसानदायक, दोनों है। ऐसे में चीनी उद्योग को नये नजरिए से देखने की जरूरत है
- चीनी उद्योग को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सी श्रेणी के शीरे से प्राप्त एथनॉल की कीमत (एक्स मिल) 1.69 रुपये बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी है, जबकि अन्य कच्चे माल के लिए दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। चीनी उद्योग के उप-उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है

स्रोत - (मीडिया इनपुट्स)

दुखद खबर: जकिया जाफरी, जिनके पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी को 2002 के गुजरात दंगों में बर्बरता से मार डाला गया था, का निधन हो गया। वर्षों वह न्याय की लड़ाई बहादुरी से लड़ीं। जब सांसद की पत्नी को इस कदर संघर्ष की नौबत आ सकती है, तो आम नागरिक पर क्या बीत सकती है, सोचा जा सकता है। लेकिन अंतिम सांस तक वे मजबूत बनी रहीं। हिम्मत नहीं हारीं। ओम शांति!

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

परिवेशगत सुधार की जरूरत

मुद्दा | विनीत नारायण

कई दशकों से देखने में आया है कि गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन कर देशवासियों को लंबे-चौड़े वादों की सौगात देकर देश का भला करने के संकल्प लिए जाते हैं परंतु इन सब से क्या देश का भला हो सकता है? कई देशों में प्रवासी भारतीयों ने कई क्षेत्रों में बुलंदियों को छुआ है। इसका मतलब हुआ कि भारतीयों में योग्यता की कोई कमी नहीं है। यदि सभी को सही मौका और प्रोत्साहन मिले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

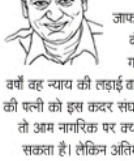

अगर यह बात सही है तो फिर क्या वजह है कि खिलाड़ियों पर खर्चा करने की बजाय खर्चीले खेल आयोजनों पर अरबों रुपया बर्बाद किया जाता है? कुछ हजार रुपये का कर्जा लेने वाले किसान आत्महत्या करते हैं और लाखों करोड़ का बैंकों का कर्जा हड़पने वाले उद्योगपति ऐश। आधी जनता भूखे पेट सोती है और एफसीआई के गोदामों में करोड़ों टन अनाज सड़ता है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया भी ऐसी अव्यवस्था का नंगा नाच दिखाने में पीछे नहीं रहते।

नतीजतन, आतंकवाद और नक्सलवाद चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। सरकार के पास विकास के लिए धन की कमी नहीं है पर धन का सदुपयोग कर विकास के कामों को ईमानदारी से करने वाल पैसे-पैसे के लिए धक्के खाते हैं और नकली योजनाओं पर अरबों रुपया डकारने वाले सरकार का धन बिना रुकावट खींच ले जाते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का क्या अर्थ लिया जाए? यही न कि हमने आजादी के नाम पर गोरे साहबों को धक्का देकर काले साहबों को बिठा दिया। पर काले साहब तो लूट के मामले में गोरों के भी बाप निकले। स्विटजरलैंड के बैंकों में सबसे ज्यादा काला धन जमा करने वालों में भारत काफी आगे है। इसलिए जरूरत है हमारी सोच में बुनियादी परिवर्तन की। 'सब चलता है' और 'ऐसे ही चलेगा' कहने वाले इस लूट में शामिल हैं। जज्बा तो यह होना चाहिए कि 'देश सुधरेगा क्यों नहीं?' 'हम ऐसे ही चलने नहीं देंगे'। अब सूचना क्रांति का जमाना है। हर नागरिक को सरकार के हर कदम को जांचने-परखने का हक है। इस हथियार का इस्तेमाल पूरी ताकत से करना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न हो उसमें में जो लोग बैठे हैं, उन्हें भी

अपना रवैया बदलने की जरूरत है। एक मंत्री या मुख्यमंत्री रात के अंधेरे में मोटा पैसा खाकर उद्योगपतियों के गैर-कानूनी काम करने में तो एक मिनट की देर नहीं लगाता। पर यह जानते हुए भी कि फलां व्यक्ति या संस्था राज्य के बेकार पड़े संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है, उसके साथ वही तत्परता नहीं दिखाता। आखिर क्यों? जब तक हम सही और अच्छे को बढ़ावा नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, उसके लिए आलोचना भी सहने से नहीं डरेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। नारे बहुत दिए जाएंगे पर परिणाम केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे। सरकारों ने अगर अपने अधिकारियों के विरोध की परवाह करते हुए अपने कार्यकालों में कई सक्षम लोगों को यदि खुली छूट न दी होती तो अमूल और मेट्रो जैसे हजारों करोड़ के साम्राज्य कैसे खड़े होते? आम आदमी के लिए रोजगार का सृजन करना हो या देश की गरीबी दूर करना हो, सरकार की नीतियों में बुनियादी बदलाव लाना होगा। केवल आंकड़े ही नहीं साक्षात परिणाम देख कर भी नीति बननी चाहिए।

खोजी पत्रकारिता के चार दशक के मेरे अनुभव यही रहे कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार बड़ी बेशर्मी से कर दिया जाता है पर सच्चाई और अच्छाई का डट कर साथ देने की हिम्मत हमारे राजनेताओं में नहीं है। इसीलिए देश का सही विकास नहीं हो रहा। खाई बढ़ रही है। हताशा बढ़ रही है। हिंसा बढ़ रही है। पर नेता चारों ओर लगी आग देख कर भी कबूतर की तरह आंखें बंद किये बैठे हैं। इसलिए फिर से समाज के मध्यम वर्ग को समाज के हित में सक्रिय होना होगा। मशाल लेकर खड़ा होना होगा। टीवी सीरियलों और उपभोक्तावाद के चंगुल से बाहर निकल कर अपने इर्द-गिर्द की बदहाली पर निगाह डालनी होगी ताकि हमारा खून खौले और हम बेहतर बदलाव के निमित्त बन सकें। विनाश के मूक द्रष्टा नहीं। तब ही हम सही मायने में आजाद हो पाएंगे। फिलहाल तो उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हैं जिनसे आजादी हासिल करने का मुगालता लिए बैठे हैं। हमारे दिमागों पर उन्हीं का कब्जा है जो घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये बातें या तो शेखचिल्ली के ख्वाब जैसी लगती हैं या किसी संत का उपदेश। पर ऐसा नहीं है। इन्हीं हालात में बहुत कुछ किया जा सकता है। देश के हजारों लाखों लोग रात दिन निष्काम भाव से समाज के हित में समर्पित जीवन जी रहे हैं। हम इतना त्याग न भी करें तो भी इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने इर्द-गिर्द की गंदगी को साफ करने की ईमानदार कोशिश करें। चाहे वह गंदगी हमारे दिमागों में हो, हमारे परिवेश में हो या हमारे समाज में हो। हम नहीं कोशिश करेंगे तो दूसरा कौन आकर हमारा देश सुधारेगा?

वसंत | श्रीराम शर्मा आचार्य

वह पावन दिन वसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य-दर्शन, उसी कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। नया भाव जगा उस प्रकाश पुंज से घनिष्ठ आत्मीयता का। उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया था। कल तक जो परिवार अपना लगता था, वह पराया होने लगा और जो प्रकाश पुंज अभी-अभी सामने आया था, वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है, वह अधिक अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं। कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राण-प्रण से पालन करना। इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्रायः साठ वर्ष से अधिक होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कुछ ननुनच किए, उनके इशारे पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही है। संभव है या नहीं, अपने बूते यह हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे? इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में उठा नहीं। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोक-हित के लिए, सत्प्रवृत्ति-संवर्धन के निमित्त होती है। उनका न कोई सगा संबंधी होता है, न उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म-विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं, अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण-विवेकानंद का, समर्थ रामदास-शिवाजी का, चाणक्य-चंद्रगुप्त का, गांधी-विनोबा का, बुद्ध-अशोक का गुरु-शिष्य संबंध स्मरण हो आया। जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ न हो, सिद्धि-चमत्कार, कौतुक-कौतूहल, दिखाने या सिखाने का क्रिया-कलाप चलता रहा हो, समझना चाहिए कि वहां गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है, और जादूगर-बाजीगर जैसा कोई खेल-खिलवाड़ चल रहा है।

रीडर्स मेल

सांच को आंच नहीं

जून, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी विदेशी के हाथ का न होने के प्रमाण सामने आ गए हैं। इन सबूतों से एक बात साबित हो गई है कि सच्चाई को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। कनाडाई आयोग की रिपोर्ट में साफ-साफ बताया गया है कि इस हत्याकांड में किसी भी विदेशी का कोई हाथ नहीं है। भारत शुरू से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप को नकारता रहा है जिसमें उन्होंने भारत को शंका की नजर से देखा था। ट्रूडो द्वारा दिए गए बयान से एक बात निकल कर सामने आती है कि बिना किसी भी ठोस आधार और तथ्यों के बिना राजनीति से प्रेरित होकर किसी भी मुल्क पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसे कृत्यों से न सिर्फ स्वयं का नुकसान होता है, बल्कि रिश्तों में भी कड़ुवाहट पैदा होती है। ट्रूडो के भारत विरोधी बयान से उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इस पूरे मामले में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर किसी भी यूरोपीय देश की भारत विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल, अब इस मामले से आगे बढ़ना होगा और दोनों मुल्कों को रिश्तों को नये सिरे से पटरी पर लाना होगा।

हितेंद्र डेढा, दिल्ली

कलंकित कर गई भगदड़

महाकुंभ में भगदड़ प्राकृतिक नहीं थी। भगदड़ आपदा के समान साबित हुई और उस व्यक्ति के लिए आपदा क्यों न हो जिसके अपने सदा के लिए खो गए। जितनी आस्था लोगों में महाकुंभ को लेकर है उतना ही विश्वास प्रशासन की व्यवस्था पर भी रहा कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती। मूल कारण चाहे जो रहे हों लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थागत खामियों के कारण ही भगदड़ मची और कुछ लोगों की जान गई। सही है कि करोड़ों की भीड़ को व्यवस्थित रखना आसान काम नहीं है। प्रशासनिक मशीनरी दिन-रात इसमें लगी हुई है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं तो लोगों को आने से ही मना कर दिया जाए। प्रशासन ने व्यवस्थाएं अच्छी कीं पर भगदड़ कलंक लगा गई। आगे से ऐसी घटना न हो, ऐसी व्यवस्था प्रशासन यदि कर लेता है, तो यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

चुनावी बजट है यह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में 12 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री की घोषणा मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाली है। इसके अलावा, सीनियर सिटीजंस को भी बजट में राहत दी गई है। महिलाओं के लिए भी दो करोड़ के टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। बजट की दूसरी बड़ी विशेषता बिहार राज्य के लिए पैकेज की घोषणाएं हैं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना और तीन ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तीन लाख के लोन को बढ़ा कर 5 लाख कर दिया गया है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने बजट को विकसित भारत और सामान्य नागरिकों का बजट बताया है। मेरा मानना है कि बजट को दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देना और बिहार के लिए विशेष पैकेज, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसकी पहली परीक्षा दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए मतदान 5 फरवरी को होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 168
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक लिपा कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी